www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 24 | गोरखपुर, 22 दिसम्बर 2024 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

विपक्षियों को मिला एक अपमान जनक मुद्दा

लीजिए, हमारे विपक्षी नेताओं को एक और अपमानजनक मुद्दा मिल गया, ताकि संसद की जनहितकारी कार्यवाही को बाधित कर दिया जाए और सड़क से संसद तक हंगामा खड़ा करके लोगों को गोलबंद किया जाए। इससे मिशन आम चुनाव 2029 की विपक्षी राह आसान हो जाएगी। बताया जाता है कि एक संसदीय चर्चा के दौरान संसद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह कह दिया है कि आजकल आंबेडकर का नाम लेना सियासी फैशन हो गया है। इतना नाम भगवान का लेते तो सात जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता।

बकौल शाह, आंबेडकर-आंबेडकर-आंबेडकर क्यों कह रहे हो? आप अगर भगवान-भगवान कहेंगे तो 7 पीढ़ियां आपकी स्वर्ग में जाएंगी।ह बस इसी बयान को लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिया है।

इस प्रकार विभिन्न दलों के समर्थन-विरोध और बचाव की सियासत के बीच संसद में धक्कामुक्की तक की नौबत आई गई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व उनके साथियों के विरुद्ध भाजपा नेताओं द्वारा एफआईआर तक दर्ज करवाना पड़ा। उधर, कांग्रेस ने भी भाजपा सांसदों के खिलाफ शिकायत दी है। इससे बिखरते इंडिया गठबंधन को थोड़ी सी राहत भी मिल गई, क्योंकि जो नेता राहुल गांधी का विरोध करते थे, वही अब उनकी भाषा पुनः बोलने लगे।

चूंकि फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव और नवम्बर 2025 में ही बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी वैतरणी पार करनी होगी, तो मुद्दा चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने मनमाफिक मुद्दा ढूंढ लिया। भाजपा ने अपनी नीतियों से मुसलमानों को उसके लिए बुक ही कर दिया है और भाजपा से दलितों को हड़पने के लिए वह संविधान बदलने से लेकर अम्बेडकर के अपमान तक के मुद्दे को हवा दे चुकी है। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस का 'दम समीकरण' दलित-मुस्लिम गठजोड़ मजबूत हो। बता दें कि इसी को मजबूत करते करते लोकजनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्व. रामविलास पासवान और उनके पुत्र केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भाजपा की गोद में जा बैठे।

वहीं, दम समीकरण की दूसरी प्रबल पैरोकार समझी गईं बसपा नेत्री और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की सियासी दुर्गति आपलोग देख ही रहे हैं, जिनपर भाजपा की बी टीम होने के आरोप लगते आए हैं। इसलिए इसी दम समीकरण पर अपना दावा मजबूत करते करते कांग्रेस क्या गुल खिलाएगी, अभी कहना जल्दबाजी होगी। क्यों-कि इसी समीकरण ने लोकसभा चुनाव 2024 में उसे 10 वर्षों के सियासी दुर्दिन से मुक्ति दिलाई है।

यह बात दीगर है कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष बनते ही उसकी सियासी सौतनों यानी इंडिया गठबंधन के साथी दलों की नींद उड़ चुकी है। इसलिए हरियाणा और महाराष्ट्र में दलितों के छिटकते ही विपक्षी आलोचना का केंद्रबिन्दु बनी कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान को ऐसा तूल दिया और आक्रामक रणनीति अपनाई कि संसद में धक्कामुक्की कांड हो गया। इससे राहुल गांधी पुनः विपक्षी नेताओं के हीरो बनते प्रतीत हो रहे हैं।

अब उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस इस मुद्दे से ही दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनावों के बाद 2027 में उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव और फिर 2028 में मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों को जीतने की रणनीति बनाएगी। चूंकि इसी बीच कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि विधानसभाओं के भी चुनाव इलेक्शन कैलेंडर के मुताबिक होंगे, इसलिए कांग्रेस जातिगत जनगणना के बाद अंबेडकर के अपमान को भी मुख्य मुद्दा बनाएगी। क्योंकि भाजपा भी इन्हीं दोनों मुद्दों पर कांग्रेस के ऊपर तार्किक सवाल उठाती आई है।

राजनीतिक टिप्पणीकारों की बातों पर गौर करें तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी के 'हत्यारोपी' हिंदूवादी नेता वीर सावरकर, और अब संविधान निमार्ता बाबा साहब डॉ भीमराम अम्बेडकर के ऊपर हुई सियासी टीका-टिप्पणी कोई नई बात नहीं है, बल्कि नई बात तो यह है कि गांधी-नेहरू का अपमान सहते रहने वाली कांग्रेस ने अम्बेडकर के अपमान को सियासी मुद्दा बनाकर एक तीर से दो शिकार कर रही है। पहला तो यह कि दलितवादी दलों और ओबीसी की राजनीति करने वाले दलों से वह मुद्दे लपक चुकी है और इसी को धार दे रही भाजपा को जन कठघरे में खड़ा करके अपना सियासी उल्लू सीधा करने की कवायद तेज कर चुकी है। अपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राममनोहर लोहिया, वीपी सिंह, लालूप्रसाद, मान्यवर कांशीराम, मायावती, रामविलास पासवान, लालकृष्ण आडवाणी, अटलबिहारी बाजपेयी आदि अनगिनत नेताओं के ऊपर सियासी टिपण्णी हुई,

लेकिन बात का इतना बतंगड़ कभी नहीं बना। कभी आजादी, कभी आरक्षण, कभी समता, कभी समरसता, कभी वामपंथ, कभी समाजवाद और कभी राष्ट्रवाद के सवाल पर सियासत हुई। रोटी कपड़ा और मकान के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की सियासत भी हुई। जय जवान, जय किसान से लेकर जय विज्ञान तक के उदघोष हुए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तक की बातें हुईं। लेकिन जनता की माली हालत उबचुब करती रही। पिछले तीन दशकों में अमीरी और गरीबी की खाई हर रोज चौड़ी हो रही है। एक और कड़वी सच्चाई यह है कि निर्वाचित नेताओं की आय रॉकेट की गति से बढ़ रही है, पर समतामूलक समाज स्थापित करने के संवैधानिक प्रयत्न नदारत रहे। क्योंकि जब भी सर्वहितकारी कुछ बात शुरू हुई तो दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को कानूनी ढाल बना दिया गया। कुछ लोगों को आरक्षण दिया गया और उनका समर्थन हासिल करके कहीं पारिवारिक राजनीति को मजबूत किया गया तो कहीं राजकोषीय लूट मचाई गई। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह कि कहीं कोई प्रशासनिक और न्यायिक संतुलन स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई। या तो कानून स्वहित के अनुरूप बने या फिर परिभाषित किये गए। दुष्प्रभाव सबके सामने है। हिंसा-प्रतिहिंसा और असमानता हमारी नियति बन चुकी है।

यह कड़वी सियासी सच्चाई यह है कि सन 1990 के दशक के पूर्वार्द्ध से देश में लागू 'नई आर्थिक नीतियों' के दुष्परिणाम स्वरूप भारतीय संसद जनहितकारी मुद्दों से अपना पिंड छुड़ाती हुई प्रतीत हो रही है और सिर्फ पूं-जीवादी एजेंडों को पूरा करने की गरज से जनमानस के बीच भावनात्मक मुद्दों को हवा दे रही है। इन नीतियों को देश में लागू करने वाली कांग्रेस और फिर बाद में उसकी समर्थक बन चुकी भाजपा (स्वदेशी आंदोलन को भूलकर) ने पूंजीवादी राजनीति को इतनी हवा दी कि क्ष-त्रीय सियासत ही हाशिए पर आ गई। इसलिए क्षेत्रीय दलों को भाजपा और कांग्रेस के इस सियासी पेंच को समझना चाहिए, लेकिन ये भी इन दोनों दलों के गठबंधन के मोहरे बन चुके हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए कि सियासत के लिए जो जरूरी आर्थिक खाद-पानी चाहिए, वो सिर्फ पूंजीवादी कम्पनियां ही पूरी कर सकती हैं। आप गौर कीजिए कि 1990 के दशक से शुरू हुए कम्पनी राज के बाद जीवन चर्या कितनी महंगी होती जा रही है। मानवीय संवेदनाओं से परे सबकुछ को मौद्रिक पैमाने पर तौलने की बाजारू प्रवृत्ति ने खान-पान, दवा-दारू, रहन-सहन से लेकर परिवहन तक को महंगा कर दिया और गुणवत्ता के मामलों में भगवान भरोसे छोड़ दिया। वहीं, कभी कांग्रेस और कभी भाजपा के बर्चस्व वाली संसद मजबूत कानूनों को पूंजीपतियों के लिहाज से कमजोर करती रही, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन आदि के क्षेत्रों में व्याप्त अराजकता बढ़ती चली गई। यह आज भी जारी है। समाज में रुपए के बढ़ते बोलबाला से प्रशासनिक तंत्र और अधिक भ्रष्ट हो गया। सियासत में ओबीसी, दलित व अल्पसंख्यक शब्दों के बढ़ते बोलबाला से जो जनप्रतिनिधियों की फौज संसद में आई, उन्होंने जाने-अनजाने सियासत को भ्रष्ट कर दिया। आलम यह है कि यथा राजा-तथा प्रजा और यथा प्रजा-तथा राजा का अंतर मिट चुका है। जनप्रतिनिधियों के विशेषाधिकार और न्यायाधीशों के न्यायिक अवमानना के अधिकारों ने मीडिया के मुंह सील दिए।

देश में अब स्वस्थ राजनीतिक बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची है। क्योंकि पहले आजादी, फिर समाजवाद, उसके बाद हिंदूवाद की सियासत हुई, जिसमें अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, जातीय तुष्टिकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, दलित-पिछड़ा-आदिवासी गोलबंदी, फिर इनकी आपसी सिरफुटौव्वल के बीच पूंजीवादी राजनीतिक अपनी जड़ जमाती रही और लोगों के मूलभूत रोजगार से लेकर जीवन यापन तक की नीतियां हाशिए पर चली गईं। अब जो भी दिखावटी जनहितकारी नीतियां लागू की जा रही हैं, उसके पीछे कॉरपोरेट लूट का एजेंडा सर्वप्रथम है, जिसे समझने में हमारे अधिकांश नेता व उनकी समर्थक अशिक्षित या कम शिक्षित जनता नाकाम रही है। आधार कार्ड, मुफ्त आवास, मुफ्त या कम ब्याज दर ऋण, डीबीटी जैसे जितने भी नव आर्थिक उपाय किए गए, सबका मकसद कम्पनियों को लाभ पहुंचना है। लोगों के पास काम नहीं है और सरकार एआई पर जोर दे रही है। सत्ता में मशीनीकरण के घुसपैठ से सिर्फ पूंजीवादियों का ही भला होगा। सच कहूं तो एक देश, एक चुनाव भी उनका ही एजेंडा है ताकि छोटे छोटे दल समाप्त हो जाएं। छोटी-छोटी कम्पनियों को उनका ऑनलाइन बाजार लूट ही चुका है। इसलिए देश जनक्रांति की बाट जोह रहा है, क्योंकि वैश्विक पूंजीवादी ताकतों के इशारे पर थिरक रही भारतीय कम्पनियों से मुट्ठी भर लोगों का भला होगा, जबकि बहुत बड़ी आबादी भावनात्मक मुद्दों पर उलझी हुई है और किसी राष्ट्रीय अभिशाप से कम नहीं है। सवाल पुनः वही कि भावनाओं को भड़काकर सियासी रोटी सेंकने की कांग्रेस-भाजपा की चाल को आखिर कबतक समझेंगे हमारे क्षेत्रीय दल और जनहित की रक्षा के लिए उनपर दबाव बढ़ाएंगे, अन्यथा एक समय बाद वो भी लोगों के बीच अप्रासंगिक हो जाएंगे।

- कमलेश पांडेय

योगी सरकार के इस फैसले से खुश हुए उत्तर प्रदेश के किसान, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के तीसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए देय मुआवजा

जेवर, (नोएडा)। जेवर के किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में 1,200 रुपये प्रति वर्गमीटर की वृद्धि की घोषणा की। राज्य सरकार के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अब दर 3,100 रुपये प्रति वर्गमीटर से संशोधित कर 4,300 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी गई है।

पर एक पोस्ट में, सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर में बनाया जा रहा है, इस विकास का श्रेय किसानों को जाता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के तीसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए देय मुआवजा 3,100 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 4,300 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है। सभी किसान भाइयों को हार्दिक बधाई और प्रणाम!

यह घोषणा सीएम योगी द्वारा एयरपोर्ट के अंतिम चरण के निर्माण के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों से बातचीत के दौरान की गई। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा, ₹किसानों को नियमानुसार ब्याज भी दिया जाएगा और प्रभावित किसानों के पुनर्वास और

उनके रोजगार की पूरी व्यवस्था की जाएगी।

किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। सीएम योगी ने कहा, ₹जेवर दशकों तक अंधेरे में डूबा रहा और अब यह विश्व पटल पर चमकने के लिए तैयार है। अगले 10 सालों में जेवर देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनने जा रहा है और पूरी दुनिया खुशहाली देखेगी। अप्रैल 2025 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे।

उन्होंने कहा कि पहले इस क्षेत्र में जमीन के लिए गोलियां चलती थीं लेकिन अब किसान खुशी-खुशी जमीन दान कर रहे हैं। इस दौरान किसानों ने कहा कि उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। सीएम योगी ने आगे कहा, जेवर एयरपोर्ट के पास एमआरओ भी विकसित किया जाएगा, जेवर विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग (एमआरओ) के लिए एक वैश्विक गंतव्य बन जाएगा। सीएम ने आगे कहा जेवर एयरपोर्ट वर्ष 2040 तक 70 मिलियन यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाला एक विशाल एयरपोर्ट होगा। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा, इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ईस्टर्न पेरिफेरल रोड, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल से होगी।

दर्दनाक मंज़र: पैर की अंगूठियों से की व्यक्ति ने अपनी पत्नी के जले हुए शव की पहचान

जयपुर। जब कन्हैयालाल मीना शुक्रवार को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल अपनी पत्नी को बस स्टॉप पर छोड़ने गए, तो उन्हें शायद ही पता था कि यह उनकी आखिरी विदाई होगी। अनीता मीना उन 14 लोगों में शामिल थीं, जिनकी मौत जयपुर-अजमेर हाईवे पर एक एलपीजी टैंकर के कई वाहनों से टकराने के बाद हुई थी, जिसके बाद भीषण आग लग गई थी, जिसमें 40 वाहन जल गए थे।

अनीता, जो चैनपुरा में आरएसी (राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी) की चौथी बटालियन में तैनात थीं, शुक्र-वार सुबह ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए दूदू से जयपुर जा रही थीं। अनीता, जो अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली थीं, सुबह 3 बजे बस में सवार हुईं।हालांकि, भांकरोटा इलाके में दुर्घटना के दौरान स्लीपर बस में आग लगने से यात्रा जानलेवा हो गई। पीड़ितों और घायलों को सवाई मान सिंह (एसएमएस)

अस्पताल ले जाया गया।

दुर्घटना की खबर मिलते ही कन्हैलाल मीना अनीता की तलाश में जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे। शुरूआत में अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि अनीता का नाम घायल यात्रियों की सूची में नहीं है। हालांकि, किसी अनहोनी की आशंका के चलते कन्हैलाल ने शवगृह की जांच की। अस्पताल में लाए गए अधिकांश शव इतने जले हुए थे कि उनकी पहचान करना मुश्किल था।

कन्हैलाल का सबसे बुरा डर तब सच साबित हुआ जब उसने एक शव पर अनीता के पैर की अंगूठियों को पहचाना। दंपति के दो छोटे बच्चे हैं। इस घटना में करीब 30 लोग घायल हुए हैं। आग पर पूरी तरह काबू पाने में दमकल विभाग को सात घंटे से ज्यादा का समय लगा। आग इतनी भयावह थी कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की लपटें करीब एक किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थीं। एक स्कूल वैन चालक ने बताया कि हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने कहा, जब मैं घटनास्थल के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि लोग जल्दबाजी में भाग रहे हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति को आग की लपटों में घिरा देखा। यह एक भयावह दृश्य था। दमकल गाड़ियां और एंबुलेंस वहां मौजूद थीं, लेकिन शुरूआत में उनके लिए घटनास्थल पर पहुंचना मुश्किल था।

नोएडा एयरपोर्ट के किसानों को बड़ा तोहफा, मुआवजा दरें बढ़ीं

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विकास के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों को राहत दी है। गत शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित संवाद में उन्होंने तीसरे चरण के भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा दर 3100 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर करने की घोषणा की। यह मुआवजा ब्याज सहित दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रभावित किसान परिवारों को व्यवस्थापन, रोजगार और सेवायोजन के अवसर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा और अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 9 दिसंबर को यहां वेलीडेशन फ्लाइट की सफल लैंडिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगले साल अप्रैल से यहां से नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सीईओ को मंच पर बुलाकर भूमि अधिग्रहण और प्रभावित किसानों के व्यवस्थापन पर चर्चा की। सीईओ ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के लगभग सभी मामलों में मुआवजा दिया जा चुका है। केवल उत्तराधिकार और वरासत के कुछ प्रकरण लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने इन मामलों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। एयरपोर्ट के साथ 40 एकड़ में एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग) हब भी बनाया जाएगा। यह क्षेत्र विमानों के रखरखाव का प्रमुख केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में यह इलाका औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का केंद्र बनेगा।जेवर, जो कभी विकास से अछूता था, अब वैश्विक मानचित्र पर चमकेगा। उन्होंने बताया कि दो वर्षों में 1334 हेक्टेयर भूमि यानी करीब 3300 एकड़ का अधिग्रहण बिना विवाद के पूरा हुआ है। यह उपलब्धि क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगी।

बानेर में लोकसेवा ई-स्कूल का उद्घाटन करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत

शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है, बल्कि अच्छे इंसान बनाने का एक व्रत : भागवत

बानेर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने गत दिनों शुक्रवार को कहा कि शिक्षा प्रणाली को सीखने में बाधा नहीं बल्कि सुविधा प्रदाता की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने बदलते समय के साथ तालमेल बिठाते हुए हमारे बुनियादी मूल्यों पर कायम रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। यहां बानेर में लोकसेवा ई-स्कूल का उद्घाटन करने के बाद आरएसएस प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है, बल्कि अच्छे इंसान बनाने का एक व्रत है।

उन्होंने कहा, शिक्षा प्रणाली को सीखने में बाधा नहीं बल्कि सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करना चाहिए। इसे केवल नियामक के रूप में कार्य करने के बजाय छात्रों को सशक्त बनाने के साधन के रूप में कार्य करना चाहिए..।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सराहना करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि इसे भले ही हाल ही में पेश किया गया हो, लेकिन इस तरह की प्रणाली के लिए कई वर्षों से चर्चा की जा रही थी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा प्रणाली पूरी तरह लागू की जाएगी और यह देश को उसकी आकांक्षाओं के सपने की ओर ले जाएगी।

क्लास इंटरवल के दौरान नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़, आरोपी स्कूल शिक्षक गिरफ्तार

झारखंड। रामगढ़ जिले में एक छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में सरकारी स्कूल के 40 वर्षीय शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 वर्षीय बच्ची के माता-पिता ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराई और शाम को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायत के अनुसार यह घटना 17 दिसंबर को भदानी नगर पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूल में हुई। इसमें कहा गया है कि घटना तब हुई जब छात्रा भोजनावकाश के दौरान शौचालय गई थी। पतरातू के अनुमण्डल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) पवन कुमार ने पीटीआई को बताया, माता-पिता ने आरोप लगाया है कि शिक्षक ने लड़की से छेड़छाड़ की और उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि मामला तब सामने आया जब नाबालिग ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। जांच जारी है।

पुस्तक विमोचनः रामामृत काव्य संकलन का हुआ विमोचन

बस्ती। प्रेस क्लब सभागार में साहित्यिक संस्था शब्द सुमन द्वारा वरिष्ठ साहित्यकार डा. त्रिभुवन प्रसाद मिश्र कृत ह्य रामामृत काव्य संकलन का लोकार्पण किया गया। इसी क्रम में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के साथ ही विशिष्ठ जनों को उनके योगदान के लिये सम्मानित किया गया।

प्रसिद्ध कवि महेश प्रताप श्रीवास्तव ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि **रामामृत काव्य संकलन** मर्यादा के राम पर केन्द्रित श्रेष्ठतम रचना है जिसे डा. त्रिभुवन प्रसाद मिश्र ने अपनी अनुभूतियों के साथ जिया है। यह कृति नई पीढी को परिवार, समाज को श्रीराम चरित के महत्व से परिचित करायेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डा. रामनरेश सिंह मंजुल ने कहा कि शब्द सुमन की पहल सराहनीय है।

डा. राम कृष्ण लाल जगमग राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों के साथ ही अपने जड़ो से जुड़े हैं और नई पौध को ऊर्जा दे रहे हैं। प्रदीप चन्द्र पाण्डेय, डा. सत्यव्रत, डा. सुशील सिंह, डा. रामकृष्ण लाल 'जगमग' ने कहा कि साहित्यिक आयोजन आज की आवश्यकता है जिससे नई पीढी संवेदनशील होने के साथ ही अपने समाज के सत्य को समझ सके। डा. वी.के. वर्मा और अंकुर वर्मा ने कहा कि रामामृत काव्य संकलन कालजयी साबित होगी।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने डा. त्रिभुवन प्रसाद मिश्र कृत **रामामृत काव्य संकलन** के विविध पक्षों पर सविस्तारचर्चा की। डा. त्रिभुवन प्रसाद मिश्र ने कहा कि उन्होने अपने राम को जिस तरह से समझा गुरू कृपा से उसे स्वर दिया।

कार्यक्रम के दूसरे चरण में वरिष्ठ साहित्यकार डा. रामकृष्ण लाल 'जगमग' के संचालन में आयोजित कवि सम्मेलन में जन कवि जमुना प्रसाद उपाध्याय ने यूं कहा-

नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाये,
तो प्यासे ओठ, एक-एक बूंद पानी को तरस जायें,
गनीमत है कि मौसम पर हुकुमत चल नहीं सकती,
नही तो सारे बादल उनके खेतों में बरस जायें

सुनाकर राजनीति पर करारा व्यंग्य किया।

डा. ज्ञानेन्द्र द्विवेदी दीपक ने कुछ यूं कहा

ऐ अब्र हमें तू बार-बार सैलाब की धमकी देता है,
हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं। सुनाकर वातावरण को नई ऊर्जा दी।

डा. हेमा पाण्डेय की रचना

पग महावर लगाया तुम्हारे लिये,
रूप मैंने सजाया तुम्हारे लिये,
सात जन्मों तलक तुम हमारे रहो,
चांद को जल चढाया तुम्हारे लिये,
सुनाकर प्रेम गीत को नया स्वर दिया।

छंद विधा के श्रेष्ठ रचनाकर सतीश आर्य ने कुछ यूं सुनाया

जब-जब अपराधिनी सिया को त्यागते हैं राम, तब-तब पनाह देती है एक झोपड़ी, सुनाकर कवि सम्मेलन को नई ऊचाई दी।

महेश प्रताप श्रीवास्तव की पंक्तियां-
बात ये है नहीं कि लोग लड़ाते हैं हमें,
बात ये है कि हम आपस में लड़ते क्यों हैं'

को श्रोताओं ने सराहा।

डा. वी.के. वर्मा ने कुछ यूं कहा -

जयचंद एक मर गया तो क्या हुआ वर्मा,
अब भी हमारे देश में जयचंद बहुत है, सुनाकर वाव वाही लूटी।

विनोद उपाध्याय 'हर्षित' की रचना-

इतनी दरिया में रवानी है अभी,
प्यास मुद्दत की बुझानी है अभी,

को श्रोताओं ने सराहा। संचालन कर रहे डा. राम कृष्ण लाल जगमग ने यूं कहा -

भारी-भारी सर लगता है,
घर भी अब बेघर लगता है,
अब तो अपने लोगों से ही
न जाने क्यों डर लगता है,

सुनाकर चिन्तन की धारा को स्वर दिया।

इसी कड़ी में प्रतिभा गुप्ता, डा. वेद प्रकाश मणि, डा. अर्चना श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव 'अश्क', डा. अफजल हुसेन अफजल, जगदम्बा प्रसाद भावुक, दीपक सिंह प्रेमी, सागर गोरखपुरी, डा. अजीत श्रीवास्तव 'राज' रहमान अली 'रहमान' आदित्यराज आदि ने सम सामयिक रचनाओं के माध्यम से वातावरण को सरस बना दिया।

इस अवसर पर साहित्यिक संस्था शब्द सुमन द्वारा कवियों और प्रबुद्धजनों अंकुर वर्मा, श्याम प्रकाश शर्मा, स्कन्द शुक्ल, राकेश गिरी, अनुराग श्रीवास्तव, सर्वेश श्रीवास्तव, सुरेन्द्र प्रताप सिंह, बी.के. मिश्र, विजय मिश्र, प्रतिभा मिश्रा आदि को उनके योगदान के लिये अंग वस्त्र, सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया।

समसामयिक रचनाओं से श्रोताओं को आह्लादित किया कवियों ने

प्रेस क्लब सभागार में साहित्यिक संस्था शब्द सुमन द्वारा आयोजित काव्य पाठ कार्यक्रम के दौरान अपनी प्रस्तुति देते कविगण

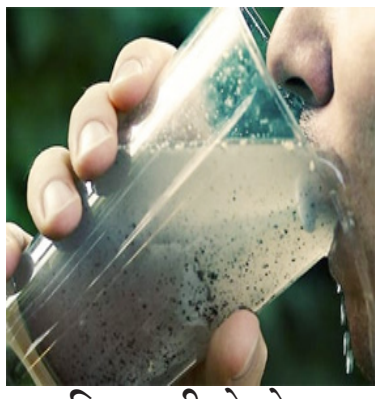

दूषित पानी से होकर गुजरने को मजबूर ग्रामीण

प्रतीत नगर ग्राम पंचायत में लंबे समय से पानी की निकासी के लिए नाली की सफाई नहीं हो पाई है। जिस–ाके चलते नाली का दूषित पानी सड़क पर बह रहा है। राहगीरों के साथ-साथ स्कूली छात्र-छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूषित पानी से छात्र-छात्राओं की ड्रेस तक खराब हो रही है।

ग्राम पंचायत प्रतीत नगर में घरों के गंदे पानी की निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया था। लेकिन ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनाई गई यह नाली ग्रामीणों के लिए ही मुसीबत का सबब बनी हुई है। लंबे समय से नाली की सफाई नहीं हुई है। जिसके चलते नाली चोक होने से दूषित पानी सड़क पर बह रहा है। सबसे खराब हालत राजकीय इंटर कॉलेज के समीप है। यहां नाली से निकलने वाला पानी इंटर कॉलेज, हनुमान चौक और छावनी के मुख्य गेट से होता हुआ रेलवे फाटक तक पहुंच रहा है। दिनभर दूषित पानी सड़क पर बहता रहता है। जिसके चलते पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दौरान तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है। जहां एक ओर दूषित पानी से स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इससे गांव में घातक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। दूषित पानी से सेना प्रशासन भी परेशान है। ग्राम पंचायत प्रतीत नगर की प्रशासक अंजना चौहान का कहना है कि गांव में किसी भी कार्य को करने के लिए पंचायत के खाते से धनराशि निकालने की अनुमति उनको नहीं मिली है। जिसके चलते गांव में विकास कार्य करने में दिक्कत आ रही है। इस समस्या के संबंध में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी अवगत कराया है। लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नही दे रहे हैं। पूर्व उप प्रधान दीवान सिंह चौहान, अजय साहू, एके सिंह और सुचित झा का कहना है कि इस मामले को लेकर जल्द ही वह जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे।

चेतुलधार के पास भूस्खलनः डीएम सहित जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे घटनास्थल पर

पिथौरागढ़। जिले के गत शनिवार सुबह करीब 9 बजे धारचूला-तवाघाट नेशनल हाईवे के चेतुलधार के पास पर भारी भूस्खलन हुआ है। धारचूला-तवाघाट एनएच के चेतुलधार के पास पहाड़ी दरकने से हाईवे बंद हो गया है। इस कारण दोनों ओर दर्जनों वाहन फंस गए है। गनीमत रही कि जिस समय पहाड़ी दरकी इस दौरान कोई भी वाहन यह से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था ।

एसडीएम मंजीत सिंह और पुलिस की टीम मौके में निरीक्षण के लिए पहुंची है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया कि धारचूला एसडीएम और बीडीओ के अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है। बीआरओ सड़क खोलने के काम में जुटा हुआ है। शीघ्र ही सड़क को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा कि पिथौरागढ़ जिले के तवाघाट-धारचूला नेशनल हाइवे पर हुई लैंडस्लाइड से यातायात प्रभावित होने की सूचना मिली है। राहत की खबर है कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मलबे को हटाने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने के साथ जिला प्रशासन व संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द मार्ग को खोलने के निर्देश दिए हैं।

जन्म दिन मुबारक हो

सीमा रंगा इन्द्रा को माता श्रीमती इन्द्रा पिता सुरत सिंह ,पति विक्की कुमार ,बेटे रितेश कुमार, केशव कुमार विवान , बहन नीशा, मुकेश सुमन, सुदेश ,शिवानी व समस्त परिवार की तरफ की जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं

त्रि-दिवसीय उत्तराखंड जनजातीय खेल महोत्सव का हुआ शुभारंभ

देहरादून। जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई) की ओर से आयोजित तीन दिवसीय उत्तराखंड जनजातीय खेल महोत्सव का शनिवार को शुभारंभ किया गया। ननूरखेड़ा स्थित पीआरडी मैदान में महोत्सव का उद्घाटन विधायक उमेश शर्मा काऊ ने किया। उन्होंने कहा, महोत्सव उत्तराखंड के आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिभा का प्रमाण है। खेल न केवल एकता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि हमारे युवाओं के लिए एक स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। कार्यक्रम की शुरूआत 24 संस्थानों की ओर से मार्च पास्ट के साथ हुई। सांस्कृतिक जीवंतता को जोड़ते हुए जनजातीय छात्रावास धनपो के छात्रों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और हरिपुर कालसी के छात्रों ने पारंपरिक घरुल नृत्य प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं। महोत्सव में 100, 200, 400, 800 और 1500 मीटर दौड़ के साथ रिले दौड़ सहित पारंपरिक और आधुनिक खेल श्रेणियों में प्रतिभागियों ने हुनर दिखाया। मुख्यमंत्री के अपर सचिव एसएस टोलिया ने कहा, यह महोत्सव समावेश और उत्कृष्टता की भावना का प्रतीक है। टीआरआई के समन्वयक राजीव कुमार सोलंकी ने कहा, हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जो न केवल हमारे आदिवासी युवाओं की एथलेटिक क्षमता को प्रदर्शित करे, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपराओं को भी बढ़ावा दे।

बाल वैज्ञानिकों ने किया अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन

देहरादून । आसरा ट्रस्ट की ओर से नालापानी रोड स्थित स्किल एबिलिटी सेंटर में ज्ञान मंथन मेले का आयोजन किया गया। इसमें राजकीय स्कूलों के हुनरमंद व स्लम बस्तियों के बच्चों ने अपनी मेधा का प्रदर्शन किया। इस खुले मंच में बच्चों ने अपनी वैज्ञानिक और गणितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन बच्चों को आसरा की टिंकरिंग लैब ने बाल वैज्ञानिक बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया है। लैब में मौजूद उपकरण और मॉडल की मदद से युवा विद्यार्थियों ने ऐसे मॉडल तैयार किए, जो भविष्य की समस्याओं को हल कर सकें। ज्ञान मंथन मेले में 30 स्कूलों के 120 बच्चों ने भाग लिया, जो तीन जिलों से आए थे। कार्यक्रम की शुरूआत अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान कुलदीप गैरोला ने की।

महाकुंभ एकजुटता सबसे बड़ा महोत्सव : चिदानंद

ऋषिकेश। अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस पर परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि विश्व में विभिन्न प्रकार के संघर्ष, आतंकवाद, युद्ध अस्थिरता फैल रही है। ऐसे में मानवता को एकजुट करने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। महाकुंभ मेला एकजुटता का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए मानव एकजुटता का सबसे बड़ा महोत्सव है। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु एकजुट होकर सामाजिक, धार्मिक, और सांस्कृतिक सौहार्द का प्रतीक बनते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष में होने वाला महाकुंभ सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। जहां लाखों लोग विभिन्न धर्म, जाति और संप्रदाय से होकर भी एक ही लक्ष्य के साथ इकट्ठा होते हैं। यह मेला एक वैश्विक मंच है। जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और धार्मिक भेदभाव को भूलकर एक ही उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं और वह है परमात्मा की कृपा प्राप्त करना, समाज में शांति व सद्भावना स्थापित करना।

गंगा की तरह होता रहे विचारों का प्रवाह : सीएम धामी

देहरादून । देवभूमि विकास संस्थान और दून विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय व्याख्यान माला गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह कार्यक्रम का शुभारंभ गत दिनों शनिवार को किया गया। विवि के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, गंगा की तरह विचारों का प्रवाह भी कभी रुकना नहीं चाहिए। विचारों का प्रवाह ही हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। सीएम धामी ने कहा, विचारों का आदान-प्रदान हमारी प्राचीन काल की संस्कृति है। वहीं, इस मौके पर उत्तराखंड में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, हिमालय क्षेत्र की धारण क्षमता एक बड़ी चुनौती है। हमें आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, पलायन रोकने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) और सशक्त भू-कानून को लागू किया जाएगा। विवि की कुलपति डॉ. सुरेखा डंगवाल ने कहा, विचारों से ही ज्ञान बढ़ता है और जहां ज्ञान है वहां शक्ति है। विद्या हमें कभी बंधनों में नहीं बांध सकती। यही वजह है कि आने वाले समय में भारत पूरे विश्व को रास्ता दिखाएगा।

सकारात्मक बनने के बजाय बनें यथार्थवादी : स्वामी अवधेशानंद

मुख्य वक्ता जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा, सकारात्मक बनने के बजाय यथार्थवादी बनें। किसी भी अवधारणा के लिए खुद को न छुपाए। उन्होंने कहा, गंगा भारत की जीवन रेखा है। गंगा की धारा की तरह हमारे विचार हमें प्रेरित करते हैं और हमारी दिशा व दशा तय करते हैं। इतना ही नहीं विचार ही व्यक्ति को मुक्त करते हैं। उन्होंने कहा, खुद से एक सवाल अवश्य करें कि मैं कौन हूं? यह भारत का विचार है। यही वजह है कि भारत ने पूरे विश्व को तमसो मा ज्योतिर्गमय का विचार दिया। उन्होंने कहा, आजकल सनातन की बहुत चर्चा है, लेकिन यह चर्चा आज की नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही है। उन्होंने आह्वान किया कि अपनी जड़ों से जुड़कर अपने परिवार व गांवों से जुड़ें। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमारे गांव भूतिया बन रहे हैं। ऐसे में दूसरे देशों और दूसरी जगह जाकर शादी व अन्य कार्यक्रम करने के बजाय अपने गांव में अपने आसपास के लोगों के साथ उत्सव मनाएं।

पेंशनर दिवस पर सम्मानित हुए 12 वरिष्ठ पेंशनर

द्वाराहाट(अल्मोड़ा)। नगर पंचायत सभागार में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन की ओर से बुधवार को पेंशनर्स दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान 12 वरिष्ठ पेंशनरों को सम्मानित किया गया। नगर पंचायत सभागार में हुई बैठक में शाखा अध्यक्ष केपीएस अधिकारी ने पेंशनरों की समस्याएं सुनीं और उन्हें गोल्डन कार्ड संबंधी समस्याओं सहित बैंक से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। इस मौके पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की ओर से बाला दत्त कांडपाल, पानदेव, नारायण दत्त जोशी, मोहन सिंह, प्रकाश खुल्वे, किशन राम, हेमा देवी आदि को सम्मानित किया गया। संचालन जेएस बिष्ट ने किया। वहां मुख्य अतिथि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल चौधरी, संरक्षक ओपी हबोर्ला, भूपाल चौहान, कृपाल राम, प्रेम राम, प्रताप सिंह मेहरा, नारायण दत्त जोशी, भुवन कांडपाल, बिपिन मठपाल मौजूद रहे।

घूँघट की बगावत

22 दिसम्बर 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

सच ही तो है- अंबेडकर जी सम्मान का विषय हैं फैशन का नहीं

भाजपा के डीएनए में प्रारंभ से ही दलित विमर्श रहा है, क्योंकि इसका मातृ संगठन आरएसएस प्रारंभ से ही ह्यसामाजिक समरसताह्व के मार्ग पर चलने वाला संगठन रहा है। इस ह्यदलित विमर्शह्व के ही डीएनए का परिणाम है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद ही इस देश में अंबेडकर जी को ह्यभारत रत्नह्व सम्मान मिल पाया। अंबेडकर जी को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया, उसने तो नेहरू जी के प्रधानमंत्री रहते नेहरू जी को और इंदिरा जी की सरकार रहते इंदिराजी को भारत रत्न दे दिया था। अंबेडकर जी, संत पेरियार, महात्मा फुले, नारायण स्वामी जैसे दलित महापुरुष संघ के प्रतिदिन होने प्रातः स्मरण मंत्र में सम्मिलित हैं। संघ के स्वयंसेवक जो भाजपा के कार्यकर्ता बनते हैं वे प्रतिदिन सुबह के अपने प्रातः स्मरण के मंत्र में अंबेडकर जी का नाम श्रद्धा से लेते हैं। संघ के वरिष्ठ प्रचारक और विश्व के सबसे बड़े मजदूर नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी तो बाबासाहेब के चुनाव में आधिकारिक एजेंट की भूमिका में रहे हैं। इस तथ्य से आप उस कालखंड में संघ व अंबेडकर जी की म्यूचुअल अंडर-स्टेंडिंग या केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। संघ के मूल चिंतन में दलित चिंता सदैव से रही है, इसका परिणाम है कि, मुंबई में जिस स्थान पर भाजपा का जन्म हुआ, उस स्थान का नाम संघ के प्रचारकों ने ह्यसमता नगरह्व रखा था। यह नाम एक बड़ा प्रतीक था भाजपा के दलित चिंतन वाले डीएनए का। बड़े दलित नेता व दलित पेंथर मूवमेंट के नेता दत्ताराव सिंदे यह सब देखकर ही भाजपा के कार्यकर्ता बने थे। संविधान पर चर्चा में देश के गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में जो कहा उसके पहले 11 स-कंड के अंश को भ्रामक रूप से देश भर में फैलाया जा रहा है। इससे कांग्रेस, अंबेडकर जी को फैशन का विषय मानने के, अपने चिर पुराने चरित्र को ही दोहरा रही है। गृहमंत्री जी के इस व्यक्तव्य को यदि पूरा सुनेंगे तो अंबेडकर जी के अपमान के सारे वहम दूर हो जाते हैं। अमित शाह ने कहा - ह्यहमे तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम आप 100 बार ज्यादा लो, लेकिन साथ-साथ अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये भी बताता हूं। अंबेडकर को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। अंबेडकर जी ने कई बार कहा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रति हो रहे व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और अनुच्छेद 370 से मैं असहमत हूं। शाह ने आगे कहा, अंबेडकर जी को आश्वासन दिया गया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया।ह्व ह्वउन्होंने कई बार कहा कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से असंतुष्ट हैं। अंबेडकर को आश्वासन दिया गया था, जो पूरा नहीं हुआ, इसलिए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बार बार संविधान और फैशन में अंबेडकर जी का नाम रटने वाली कांग्रेस ने तो बाबा साहेब को संविधान सभा के 296 सदस्यों में अंबेडकर जी को प्रवेश तक भी न मिलने देनें हेतु षड्यंत्र रचे थे। बाद में दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल के सहयोग से वे येन केन प्रकारेण संविधान सभा में प्रवेश कर पाये थे। अंबेडकर जी बंगाल की जिस खुलना जैसोर सीट से संविधान सभा में पहुँचे थे वह इकहत्तर प्रतिशत हिंदू बहुल थी। देश विभाजन में ईक्कावन प्रतिशत हिंदू बहुल वाले क्षेत्रों को भारत में रहने देना तय हुआ था। केवल बाबासाहेब को संविधान सभा में घुसने से रोकने के लिए कांग्रेस ने बंगाल का यह इकहत्तर प्रतिशत वाला जिला पाकिस्तान को दे दिया था ताकि अंबेडकर जी की संविधान सभा की सदस्यता रद्द हो जाए। आज अंबेडकर जी का नाम फैशन में लेने वाली कांग्रेस ने तो अंबेडकर जी का चित्र तक लोकसभा में नहीं लगने दिया था। संसद में, गैरकांग्रेसी सरकार बनने पर ही अंबेडकर जी का चित्र लग पाया था। भाजपा ने अंबेडकर जी से जुड़े पाँच स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। बाबासाहेब लंदन में जिस घर में रहे, भाजपा सरकार ने उसका भी अधिग्रहण किया व उनके स्मारक के रूप में उसे लंदन तक में विकसित किया। भाजपा ने ही चैत्य भूमि को विकसित किया और प्रधानमंत्री मोदी वहाँ स्वयं प्रार्थना करने हेतु गए। भाजपा ने दिल्ली के 26, अलीपुर रोड को भी विकसित किया जहां बाबासाहेब ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। देश विभाजन की जनक कांग्रेस के सामने बाबासाहेब प्रारंभ से ही अखंड भारत के पक्ष में थे। यह नेहरू जी को बहुत भयभीत करता था। नेहरू जी वे अंबेडकर जी की प्रतिभा को जानते थे अतः वे उन्हें सत्ता की दहलीज तक भी नहीं आने देना चाहते थे। अंबेडकर जी मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए किए जा रहे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के पुरजोर विरोध में थे। अंबेडकर जी की पुस्तक ह्वथॉट्स ऑन पाकिस्तानह्व में इसका पूरा विवरण है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ह्वमुस्लिम तुष्टिकरणह्व की नीति के चलते कांग्रेस ने देश का विभाजन कर डाला। बाबासाहेब का यह स्पष्ट मानना था कि चूँकि धर्म आधारित विभाजन हुआ है अतः संपूर्णतः ह्वतुम उधर-हम इधरह्व की नीति अपनाई जानी चाहिए। बाबासाहेब ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में भारत के धार्मिक आधार पर पूर्ण विभाजन के आशय से पृष्ठ 103 पर लिखा ह्वयह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान बनने से हिंदुस्तान सांप्रदायिक समस्या से मुक्त नहीं हो जाएगाह्व। अंबेडकर जी के इन्ही मुस्लिम विरोधी विचारों के कारण से ह्यमुस्लिम तुष्टिकरण में लगे नेहरू जी व गांधी जीह्व अंबेडकर जी को आगे नहीं आने देना चाहते थे। इसी क्रम में मुंबई से दो बार अंबेडकर जी को चुनाव में षड्यंत्रपूर्वक हरवाया गया। इन दोनों बार के चुनावों में अंबेडकर जी की पराजय को सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री नेहरू जी ने स्वयं मुंबई जाकर चुनाव प्रचार किया था व अपने विरोधी दलों से भी अंबेडकर जी को पराजित कराने हेतु मित्रतापूर्ण संबंध बनाए थे। आज जो कांग्रेस और कुछ अन्य दल अंबेडकर जी का नाम फैशन में या सत्तामोह में ले रहें हैं उन्हें इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि अंबेडकर जी केवल और केवल सम्मान का विषय हैं फैशन का नहीं!

अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धा राष्ट्र दृष्टिकोण में, न कि नाम जपने में

बाबासाहेब अम्बेडकर की विरासत पर चल रहा राजनीतिक विवाद, इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे राजनेता, विशेष रूप से प्रमुख जातियों के, जाति-आधारित भेदभाव को सम्बोधित किए बिना इसका शोषण करते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि दलित केवल पहचान के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, समानता और अवसरों के लिए लड़ते हैं और राष्ट्र के लिए अम्बेडकर के दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अम्बेडकर के समर्थकों द्वारा ईश्वर की गलत खोजह्व के बारे में हाल ही में की गई टिप्पणियों ने आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था की निरंतरता पर चचाओं को फिर से हवा दे दी है। इन टिप्पणियों ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या वे जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ दशकों से चल रही सक्रियता को कमजोर करती हैं। बी.आर. अम्बेडकर के विचार और दृष्टिकोण अत्यधिक प्रासंगिक बने हुए हैं, जो न केवल दलितों के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अम्बेडकर के सिद्धांतों को चुनिंदा रूप से अपनाना और हाशिए पर पड़े समूहों से सम्बंधित मुद्दों पर अपर्याप्त ध्यान उनके मिशन के सार को कमजोर करता है। अम्बेडकर को देवता बनाने की प्रथा सामाजिक परिवर्तन और दलित समुदाय को सशक्त बनाने में उनके अपार योगदान में निहित है।

राजनेता, जिनमें से अधिकांश प्रमुख जातियों से हैं, जातिगत भेदभाव को सम्बोधित किए बिना अंबेडकर की विरासत पर बहस कर रहे हैं। कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से अंबेडकर की पहल का विरोध किया, आरक्षण और मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया। पार्टी ने जातिगत वास्तविकताओं को सम्बोधित करने के बजाय दलितों को एक गरीब वर्ग (ह्वगरीब जनताह्व) के रूप में माना। बजट आवंटन के बावजूद दलितों को अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो 50-60 साल पहले की तरह ही है। अंबेडकर की विरासत पर संसद की बहस प्रमुख जाति के राजनेताओं के बीच जातिगत प्रवचन की सतहीता को उजागर करती है। बुलंद बयानबाजी के बावजूद, जाति-आधारित भेदभाव प्रणालीगत बना हुआ है, जिसका सबूत दलितों के खिलाफ हिंसा जैसी चल रही घटनाओं से मिलता है। दलितों के मुद्दों को उठाने में इंडिया ब्लॉक की तीव्रता हाशिए पर पड़े समूहों के संघर्षों की वास्तविक समझ की कमी के विपरीत है। सरकार ने महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 जैसी पहल की है। इसने अंबेडकर की विरासत का सम्मान करने के लिए पंच तीर्थ स्थलों का निर्माण करके दलितों की गरिमा पर जोर दिया। ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य दलितों सहित हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाना है। हाल के वर्षों में भाजपा में दलितों का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ा है। इन प्रयासों के बावजूद, जाति-आधारित भेदभाव जारी है, जिसमें दलित व्यक्ति पर पेशाब करने जैसी घटनाएँ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम और पंच तीर्थ स्थलों का उद्देश्य दलितों के सम्मान और विमर्श को ऊपर उठाना है। भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर दलित नेताओं को अभूतपूर्व रूप से शामिल किया है।

अंबेडकर के विचार दलितों से परे हैं, जो सभी हाशिए पर पड़े समूहों के लिए भेदभाव और असमानता का समाधान प्रस्तुत करते हैं। ध्यान अस्तित्व से हटकर समान अवसर और शासन और प्रशासन में प्रतिनिधित्व की आकांक्षाओं पर केंद्रित हो गया है। अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धा राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को अपनाने में निहित है, न कि केवल उनका नाम जपने या उनकी छवि का आह्वान करने में। बाबासाहेब अंबेडकर एक पूजनीय व्यक्ति बने हुए हैं, जो दलितों की सम्मान और समानता की आकांक्षाओं के केंद्र में हैं। उनकी विरासत दलितों से आगे तक फैली हुई है, जो भेदभाव और राष्ट्र निर्माण पर व्यापक चचाओं को प्रभावित करती है। दलित केवल पहचान की राजनीति से परे समान अवसर, शासन में समानता और अपनी आकांक्षाओं के लिए सम्मान चाहते हैं। उनका संघर्ष आकांक्षा और राष्ट्रीय समावेशिता के व्यापक विषयों को शामिल करता है। दलित पहचान के संकट से नहीं जूझ रहे हैं; उनका संघर्ष सम्मान, मान्यता, अवसर और समानता पर केंद्रित है। अंबेडकर से लेकर कांशीराम, मायावती और रामविलास पासवान जैसे नेताओं तक, दलित आंदोलन लचीलेपन और आकांक्षाओं की विरासत पर आधारित है। दशकों से तुष्टिकरण की राजनीति ने दलितों को वंचित रखा है, कुछ लाभ प्रदान किए हैं जबकि समानता की उनकी आकांक्षाओं को दबा दिया है। अंबेडकर की विरासत पर बहस आधुनिक भारत में जातिगत भेदभाव की निरंतरता को रेखांकित करती है। जाति मानव समानता और सम्मान के साथ सबसे महत्त्वपूर्ण विश्वासघात बनी हुई है, जो सच्ची सामाजिक प्रगति में बाधा डालती है। जाति-आधारित पूर्वाग्रहों को चुनौती देने और समुदायों में आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अभियानों और शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करें। भेदभाव विरोधी कानूनों को लागू करें और जाति-आधारित हिंसा और असमानता के लिए कठोर दंड का प्रावधान करें। दलितों और अन्य हाशिए के समूहों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच का विस्तार करें। सामूहिक गौरव को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर अंबेडकर जैसे दलित नेताओं के योगदान को पहचानें और उनका सम्मान करें। शिकायतों को दूर करने और विश्वास बनाने के लिए समुदायों के बीच खुली चर्चा की सुविधा प्रदान करें। राजनीतिक नेताओं से विभाजनकारी बयानबाजी से बचने और सामाजिक न्याय के लिए नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करें। समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए शासन, शिक्षा और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाएँ। हाशिए के समुदायों के भीतर समानता और सम्मान की वकालत करने वाली स्थानीय पहलों का समर्थन करें।

प्रियंका सौरभ

सरकार ने महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 जैसी पहल की है। इसने अंबेडकर की विरासत का सम्मान करने के लिए पंच तीर्थ स्थलों का निर्माण करके दलितों की गरिमा पर जोर दिया। ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य दलितों सहित हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाना है। हाल के वर्षों में भाजपा में दलितों का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ा है। इन प्रयासों के बावजूद, जाति-आधारित भेदभाव जारी है, जिसमें दलित व्यक्ति पर पेशाब करने जैसी घटनाएँ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम और पंच तीर्थ स्थलों का उद्देश्य दलितों के सम्मान और विमर्श को ऊपर उठाना है। भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर दलित नेताओं को अभूतपूर्व रूप से शामिल किया है। अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धा राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को अपनाने में निहित है, न कि केवल उनका नाम जपने या उनकी छवि का आह्वान करने में। बाबासाहेब अंबेडकर एक पूजनीय व्यक्ति बने हुए हैं, जो दलितों की सम्मान और समानता की आकांक्षाओं के केंद्र में हैं। उनकी विरासत दलितों से आगे तक फैली हुई है, जो भेदभाव और राष्ट्र निर्माण पर व्यापक चचाओं को प्रभावित करती है।

बिस्मिल कोई व्यक्ति नहीं आजाद भारत की आत्मा

गोरखपुर (जीकेबी)। चौधरी चरण सिंह ग्राम्य विकास संस्थान के तत्वावधान में बिस्मिल पार्क में आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का शहादत दिवस मनाया गया। बतौर मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए गोरखपुर छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम सिंह ने कहा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कोई व्यक्ति नहीं आजाद भारत की आत्मा हैं। उन्होंने देश पर कुर्बान होने वाले ऐसे नौजवानों की खेप तैयार की जिनकी दिवानगी भारत की फिजाओं में तब तक रहेगी जब तक यह देश जिंदा रहेगा । विशिष्ट वक्ता के रूप में बोलते हुए ट्रेड यूनियन नेता ए के सिंह ने कहा कि बिस्मिल और क्रांति एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैजो संघर्ष की भी में तपता है वो बिस्मिल बनता है ।

योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व का विशेष पक्ष बाल प्रेम

गोरखपुर । अनुशासित शासन व्यवस्था के लिए देश-दुनिया में सुप्रसिद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व का एक खास पहलू है, बाल प्रेम। देश के भविष्य के बीच सीएम योगी, वर्तमान के अपने निजी व्यस्तता में भी समय निकाल ही लेते हैं। प्रोट-ोकॉल से इतर मुलाकात, प्यार-दुलार, आशीर्वाद के बीच बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी बातें करना उन्हें आत्मीय संतोष देता है। तभी तो कानून व्यवस्था को लेकर सख्त छवि वाले मुख्यमंत्री से मिलकर बच्चे चहक उठते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाल प्रेम और बच्चों के साथ परस्पर जुड़ाव की अनुभूति का एक दृश्य शनिवार दोपहर बाद गोरखपुर सर्किट हाउस परिसर में जीवंत हुआ। सीएम योगी आजीविका मिशन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोरखपुर आए। इसे लेकर शनिवार को गोरखपुर सर्किट हाउस परिसर के हेलिपैड पर प्रोटोकॉल और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी।

इसी बीच जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर यहां लैंड हुआ, परिसर से सटे और एक बंद गेट से उस पार पड़ने वाले आंबेडकर पार्क में पिकनिक मनाने आए स्कूली बच्चों का उत्साह और उल्लास आसमान छूने लगा। हवा में लहराते सैकडों बच्चों के हाथ देख और बालकंठ से समवेत गुंजित अभिवादन की आवाज सुन सीएम योगी पहले से तय कार्यक्रम स्थल (योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह) जाने की बजाय मुस्कुराते हुए बच्चों के पास पहुंच गए। फिर शुरू हुआ वही सिलसिला जो मुख्यमंत्री को अलहदा बनाती है। बाल प्रेम, बच्चों के लिए प्रोट-ोकॉल से बेपरवाह। आंबेडकर पार्क के बंद गेट के पास बच्चों को प्यार-दुलार, खूब पढ़ने का आशीष तो जमकर हंसी ठिठोली भी। अकस्मात इस आत्मीय मुलाकात-संवाद के बीच बंद गेट से कई बच्चों ने मुख्यमंत्री की तरफ हाथ बढ़ा दिया और सीएम योगी ने भी बिना पल गंवाए अभिभावक सरीखे होकर उनके हाथ थाम लिए।

अन्वेषण करें, सीखें और प्रेरित हों

भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाई जाती है। गणितज्ञों ने रामानुजन की प्रतिभा की तुलना 18वीं और 19वीं सदी के जैकोबी और यूलर जैसी हस्तियों से की है। संख्या सिद्धांत में उनके योगदान को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, और उन्होंने विभाजन कार्य को आगे बढ़ाया। 2012 से, 22 दिसंबर को भारत के राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कई शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं। 2017 में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कुप्पम में रामानुजन मठ पार्क के उद्घाटन से इस दिन का महत्व बढ़ गया था। श्री रामानुजन और अन्य गणित प्रेमी दुनिया भर में पाए जाते हैं, और कुछ लोग इस विषय के बारे में और अधिक जानने में दूसरों की मदद भी करते हैं। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उल्लेखनीय विरासत का सम्मान करते हुए, बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 मनाया जा रहा है। दिन दिलचस्प गतिविधियों से भरा हुआ था, जिसमें दैनिक जीवन में गणित के महत्व पर जोर दिया गया था। इंटरैक्टिव सेमिनारों, अंकगणितीय क्विज और समस्या-समाधान अभ्यासों से छात्रों का उत्साह और संख्याओं के प्रति प्रेम बढ़ा। भविष्य को आकार देने में गणितीय अवधारणाओं के महत्व पर चर्चा करने के लिए अतिथि शिक्षकों द्वारा एक विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई। राष्ट्रीय गणित दिवस का इतिहास भारत में गणित दिवस के संस्थापक प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन हैं, जिनके योगदान ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समाज को प्रभावित किया है। रामानुजन का जन्म 1887 में तमिलनाडु के इरोड में एक अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने स्वयं के कई प्रमेय विकसित किए और न्यूनतम औपचारिक शिक्षा के बावजूद बारह साल की उम्र में त्रिकोणमिति में पारंगत हो गए। 14 साल की उम्र में, रामानुजन अपना घर छोड़कर भाग गए और मद्रास के पचैयप्पा कॉलेज में दाखिला लिया। रामानुजन फेलो ऑफ आर्ट्स की डिग्री के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने में असमर्थ थे क्योंकि, अपने साथियों की तरह, वे अन्य विषयों में समान सफलता प्राप्त किए बिना केवल गणित में ही सफल हुए। अत्यधिक गरीबी के बावजूद रामानुजन ने गणित में स्वतंत्र शोध करने का निर्णय लिया। महत्वाकांक्षी गणितज्ञ ने तुरंत चेन्नई के गणित की ओर ध्यान आकर्षित किया। इंडियन मैथमैटिकल सोसाइटी के संस्थापक, रामास्वामी अय्यर ने उन्हें 1912 में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्कशिप हासिल करने में मदद की। उसके बाद, रामानुजन ने अपना काम ब्रिटेन में गणितज्ञों को भेजना शुरू किया। कैम्ब्रिज के जीएच हार्डी नामक गणितज्ञ रामानुजन के प्रमेयों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें 1913 में लंदन आमंत्रित किया। 1914 में, रामानुजन ने ब्रिटेन की यात्रा की, जहाँ हार्डी ने उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में दाखिला लेने में मदद की। 1917 में लंदन मैथमैटिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद रामानुजन सफलता की राह पर थे। उन्हें 1918 में रॉयल सोसाइटी का फेलो भी बनाया गया, जिससे वह यह सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक बन गए।

राष्ट्रीय गणित दिवस का महत्व आइए राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 के बारे में विस्तार से देखें: राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 पर त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ें। रामानुजन ने त्रिकोणमिति प्रमेय स्वयं विकसित किए। यह अब तक के सर्वश्रेष्ठ गणितीय आविष्कारों में से एक है। 2024 में राष्ट्रीय गणित दिवस पर रामानुजन फिल्म देखने पर विचार करें। फिल्म में रामानुजन के जीवन को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। जैसा कि रामानुजन ने दिखाया है, प्रत्येक छात्र में अद्वितीय ताकत और कमियां होती हैं। हालाँकि अपना सर्वश्रेष्ठ करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, ऐसे बच्चे की मदद करना और उसे प्रोत्साहित करना न भूलें जो असाधारण रूप से अच्छा करता हैविशेष विषय। राष्ट्रीय गणित दिवस उल्लेखनीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का सम्मान और जश्न मनाता है, जिन्होंने अन्य विषयों में संघर्ष करने के बाद अपने दम पर गणित का अध्ययन करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। गणित दिवस की समयरेखा 1887 (रामानुजन का जन्म हुआ): एक महान गणितज्ञ जिन्होंने अनुशासन पर अमिट प्रभाव डाला, रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरोड में एक गरीब अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1918 (एक उच्च उपलब्धि): ब्रिटेन में लंदन मैथमैटिकल सोसाइटी में शामिल होने के लिए चुने जाने के तुरंत बाद, रामानुजन इतिहास में रॉयल सोसाइटी के फेलो नामित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्तियों में से एक बन गए। 2012 (गणित दिवस को मान्यता दी गई): रामानुजन की उपलब्धियों के सम्मान में, पूर्व भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर, रामानुजन के जन्म के दिन, को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया। 2019 (द रॉयल सोसाइटी ऑनर्स रामानुजन): प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने साथी के सम्मान में एक विशेष संदेश ट्वीट किया। त्रिकोणमिति के बारे में 5 आश्चर्यजनक तथ्य मौलिक पहचान आठ त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ हैं जिन्हें मौलिक सर्वसमिकाएँ कहा जाता है, उनमें से तीन को पाइथागोरस सर्वसमिकाएँ कहा जाता है क्योंकि वे पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित हैं। एक प्राचीन गणना तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, खगोल विज्ञान अनुसंधान में ज्यामिति के उपयोग के परिणामस्वरूप त्रिकोणमिति का विकास हुआ। संगीत के रूप में गणित एक एकल नोट को साइन वक्र पर दर्शाया जा सकता है, एक तार को एक दूसरे के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने वाले कई साइन वक्रों के साथ दर्शाया जा सकता है, और ध्वनि तरंगें दोहराए जाने वाले तरंग पैटर्न में यात्रा करती हैं जिन्हें ग्राफिक रूप से साइन और कोसाइन कार्यों द्वारा दर्शाया जा सकता है। त्रिकोणमिति का संगीत से गहरा संबंध है और यह संगीत सिद्धांत और उत्पादन का एक प्रमुख घटक है। त्रिकोणमिति हमें नेविगेट करने में मदद करती है यदि 1700 के दशक में हमारे पास त्रिकोणमिति होती, तो संभवतः हम एक जहाज के नाविक होते। थोड़ी सी त्रि-ाकोणमिति और एक अच्छी घड़ी के साथ, एक कुशल नाविक अटलांटिक महासागर के बीच में भी अपनी स्थिति का पता लगा सकता है।

विजय गर्ग,
मलोट

देश के पंजाब राज्य में तो हालात बहुत खराब स्थिति में पहुंच गए है एवं वहां ग्रामीण इलाकों में भी युवा विभिन्न प्रकार के व्यसनों में लिप्त पाए जा रहे हैं। नशे के सेवन से न केवल स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है बल्कि मानसिक तौर पर भी युवा वर्ग विक्षिप्त अवस्था में पहुंच जाता है।

भारतीय युवाओं का भटकना देश की गंभीर समस्या

आज भारत के विभिन्न कस्बों, नगरों, विशेष रूप से महानगरों में, कम उम्र के नागरिकों के बीच व्यसन की समस्या विकराल रूप धारण करती हुई दिखाई दे रही है। देश के कुछ भागों में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। भारत का युवा यदि गलत दिशा में जा रहा है तो यह भारत के भविष्य के लिए अत्यधिक चिन्ता का विषय है। देश के पंजाब राज्य में तो हालात बहुत खराब स्थिति में पहुंच गए है एवं वहां ग्रामीण इलाकों में भी युवा विभिन्न प्रकार के व्यसनों में लिप्त पाए जा रहे हैं। नशे के सेवन से न केवल स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है बल्कि मानसिक तौर पर भी युवा वर्ग विक्षिप्त अवस्था में पहुंच जाता है।

मेडिकल साइन्स के अनुसार, ड्रग्स के लंबे समय तक सेवन से लिवर, फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। ड्रग्स का सेवन इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, जिससे व्यक्ति आसानी से बीमार पड़ सकता है। अत्यधिक मात्रा में ड्रग्स लेने से व्यक्ति कोमा में जा सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रकार ड्रग्स के सेवन से डिप्रेशन, एंग्जायटी, और सि-जोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति को चूंकि इनकी लत लग जाती है अतः वह व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से ड्रग्स पर निर्भर हो जाता है।

ड्रग्स के आदी व्यक्ति का व्यवहार भी आक्रामक हो जाता है, जिसके कारण परिवार में तनाव और झगड़े बढ़ जाते हैं। ड्रग्स पर पैसा खर्च करने से व्यक्ति और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी डावांडोल होने लगती है।

ड्रग्स को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, यदि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी हो और युवाओं को परिवार से धन की प्राप्ति नहीं होती है तो ड्रग्स की लत के कारण युवा चोरी, लूटपाट या अन्य अवैध गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। यह स्थिति भारत के लिए ठीक नहीं कही जा सकती है क्योंकि एक तो उस युवा का देश के विकास में योगदान लगभग शून्य हो जाता है, दूसरे, वह व्यक्ति अपने परिवार एवं समाज पर बोझ बन जाता है।

हम अक्सर मदिरापान और धूम्रपान की स्थिति में कैंसर का डर दिखाकर तम्बाकू निषेध को लक्षित करते हैं। जबकि व्यसनों के कई प्रकार हैं। ड्रग्स के विभिन्न प्रकार और उनके प्रभावों को समझना जरूरी है ताकि इसके दुरुपयोग से बचा जा सके।

ड्रग्स से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाकर ही एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण किया जा सकता है। आज देश में ड्रग्स की उपलब्धता बहुत आसान हो गई है। कई अंतरराष्ट्रीय गिरोह भारतीय युवाओं को अपनी गिरफ्त में लेकर कई प्रकार के ड्रग्स आसानी से उपलब्ध कराते हैं और उन्हें इनका आदी बना देते हैं। ड्रग्स के भी कई प्रकार हैं। जैसे-

डिप्रेसेंट्स : इस श्रेणी में अल्कोहल, बार्बिट्युरेट्स, बेंजोडायजेपाइन आदि को शामिल किया जाता है। इस प्रकार के ड्रग्स मस्तिष्क की गतिविधि को धीमा कर देते हैं, जिससे व्यक्ति को शांति या सुकून महसूस होता है। लेकिन, अधिक मात्रा में लेने से यह सांस की तकलीफ, बेहोशी और मृत्यु का कारण बन सकते हैं।

स्टिमुलेंट्स : इस श्रेणी में कोकीन, मेथामफेटामिन, कैफीन आदि को शामिल किया जाता है। यह ड्रग्स मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की गतिविधि को बढ़ाते हैं, जिससे चुस्ती और ऊर्जा बढ़ती है। इसके अधिक सेवन से दिल की धड़कन तेज होना, हाई ब्लड प्रेशर, और घबराहट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

ओपिओइड्स : हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन आदि को इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। इस प्रकार के ड्रग्स दर्द निवारक दवाएं हैं, लेकिन नशे के रूप में इनका दुरुपयोग किया जाता है। ओपिओइड्स का अधिक सेवन श्वसन तंत्र को धीमा कर देता है, जिससे व्यक्ति कोमा या मृत्यु का शिकार हो सकता है।

साइकेडेलिक्स : एलएसडी, साइलोसाइबिन (मशरूम), डीएमटी आदि ड्रग्स इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं एवं इस प्रकार के ड्रग्स व्यक्ति की धारणा, विचार और मूड को बदल देते हैं। यह मतिभ्रम पैदा कर सकते हैं।

इनहेलेंट्स : पेट्रोल, गोंद, स्प्रे पेंट आदि को इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। इन पदार्थों को सूंघकर नशा किया जाता है। यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं।

कैनाबिनोइड्स: गांजा, भांग, हशीश आदि को इस श्रेणी के ड्रग्स में शामिल किया जाता है। इस प्रकार के ड्रग्स सुखद अनुभव कराते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में लेने से मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

इस प्रकार से देश में ड्रग्स की समस्या विकराल रूप धारण करती दिखाई दे रही है एवं इसने विशेष रूप से युवाओं को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। दरअसल युवा, फिल्मों आदि को देखकर इसके सेवन को उचित मानने लगता है एवं इसके सेवन से समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास करता है।

उसे लगता है कि उच्च सोसायटी में नशे का सेवन करना जैसे आम बात है। परन्तु, नशे से होने वाले नुक्सान से सर्वथा अनभिज्ञ रहता है। इसलिए विशेष रूप से युवाओं को नशे की लत से छुड़ाना अति आवश्यक है। हालांकि, हाल ही के समय में नशे की समस्याओं से युवा किस प्रकार परेशानी का सामना करता है जैसे विषयों को लेकर कई फिल्में भी बनाई गई हैं, इन्हें देखकर युवाओं में जागरूकता पैदा की जा सकती है। उड़ता पंजाब (2016), इस फिल्म में पंजाब में ड्रग्स की समस्या और उससे जूझते युवाओं की कहानी है।

संजू (2018), इस फिल्म में युवाओं में ड्रग्स की लत और उससे बाहर निकलने की कहानी को दिखाया गया है। फैशन (2008), इस फिल्म में एक मॉडल को दिखाया गया है, जो शोहरत की दुनिया में ड्रग्स की लत का शिकार हो जाती है। डरना जरुरी है (2006), इस फिल्म की कहानी एक विशेष ड्रग एडिक्शन पर केंद्रित है। तमाशा (2015), इस फिल्म में नशे और आत्म-खोज की चुनौती को दर्शाया गया है। इसी प्रकार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ फिल्मे बनाई गईं है।

आज का युवा चूंकि फिल्मों की ओर अधिक आकर्षित होता है अतः व्यसनों से छुटकारा पाने के सम्बंध में बनाई गई फिल्मों का वर्णन किया गया है। परंतु, युवाओं को नशामुक्त करने की दृष्टि से विभिन्न संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान चलाना आज आवश्यक हो गया है। सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों पर व्यसन के दुष्प्रभावों पर आधारित जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। फिल्म फेस्टिवल, नुक्कड़ नाटक, सेमिनार, और सोशल मीडिया का उपयोग कर व्यसनों के नुक-सान के बारे में युवाओं को जानकारी दी जा सकती है। स्कूलों और कॉलेजों में नशा विरोधी शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए जिससे छात्रों को छोटी उम्र से ही व्यसनों के खतरों के बारे में शिक्षित किया जा सके। नशे से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर इतनी सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए कि वह समाज के सामने उदाहरण बने। अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री पर निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए एवं दोषियों पर कठोर दंड लागू किया जाना चाहिए। विभिन्न कस्बों एवं नगरों में स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहे एनजीओ और समुदाय आधारित संगठनों को नशमुक्ति अभियान में शामिल किया जाना चाहिए। यह संगठन व्यसन पीड़ितों की पहचान कर उन्हें उचित सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। परिवारों को व्यसन से बचाव और इसके लक्षणों की पहचान करने के तरीकों पर शिक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए माता-पिता को उनके बच्चों के व्यवहार पर ध्यान देने और संवाद बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

व्यसन मुक्त भारत बनाने के लिए युवाओं को खेल, संगीत, नृत्य, और अन्य सृजनात्मक गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। इससे वे सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहेंगे और व्यसन से दूर रहेंगे। युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए ताकि उन्हें सकारात्मक दिशा मिले और वे व्यसन से दूर रहें।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है एवं विजयादशमी 2025 को 100 वर्ष का महान पर्व सम्पन्न होगा। संघ के स्वयंसेवक समाज में अपने विभिन्न सेवा कार्यों को समाज को साथ लेकर ही सम्पन्न करते रहे हैं। अतः इस शुभ अवसर पर, भारत के प्रत्येक जिले को, अपने स्थानीय स्तर पर समाज को विपरीत रूप से प्रभावित करती, समस्या को चिन्हित कर उसका निदान विजयादशमी 2025 तक करने का संकल्प लेकर उस समस्या को अभी से हल करने के प्रयास प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

किसी भी बड़ी समस्या को हल करने में यदि पूरा समाज ही जुड़ जाता है तो समस्या कितनी भी बड़ी एवं गम्भीर क्यों न हो, उसका समय पर निदान सम्भव हो सकता है। अतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक स-ांस्कृतिक संगठन होने के नाते, समाज को साथ लेकर भारत को व्यसन मुक्त बनाने हेतु लगातार प्रयास कर रहा है।

इसी प्रकार, अन्य धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों को भी आगे आकर विभिन्न नगरों में इस प्रकार के अभियान चलाना चाहिए।

तात्कालिक उपायों के साथ दीर्घकालीन उपायों पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी

पिछले माह आरबीआई ने 2-11नवम्बर,2024 में परिवारों को महंगाई को लेकर कैसी उम्मीदें हैं, इस विषय पर सर्वेक्षण कराया था। आरबीआई के सर्वेक्षण से अंदाजा मिलता है कि सितम्बर, 2024 के चरण की तुलना में नवम्बर के सर्वेक्षण में शामिल प्रतिभागियों में एक बड़े वर्ग को लगता है कि नये साल 2025 में कीमतें और महंगाई दोनों ही बढ़ेंगी। यह बढ़ोतरी मुख्य तौर पर खाद्य वस्तुओं और घर से जुड़े खर्चों के बढ़ते दबाव की वजह से होगी।

इस बीच उपभोक्ता आत्मविश्वास सर्वेक्षण से अंदाजा मिला है कि सर्वेक्षण के प्रतिभागियों की मौजूदा कमाई की धारणा में भले ही कमी आई हो लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद है कि भविष्य में आमदनी बढ़ेगी, रोजगार की स्थिति में भी सुधार आएगा। निस्संदेह खाद्य पदार्थों की महंगाई रोकने के लिए सरकार द्वारा तात्कालिक उपायों के साथ दीर्घकालीन उपायों पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी होगा। इस समय ग्रामीण भारत में जल्द खराब होने वाले ऐसे कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करने पर प्राथमिकता से काम करना होगा, जिनकी खाद्य महंगाई के उतारझचढ़ाव में ज्यादा भूमिका होती है। ऐसे में सरकार को खाद्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कृषि उपज की बबार्दी रोकने के बहुआयामी प्रयासों के तहत खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग की कारगर व्यवस्था की डगर पर बढ़ना होगा। आशा है कि आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा सरकार के साथ आरबीआई के विभिन्न समन्वित रणनीतिक प्रयासों से महंगाई को नियंत्रित करने और सुस्त विकास दर को बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। इससे आरबीआई के लक्ष्य के मुताबिकङ्क खुदरा महंगाई दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 4.5 प्रतिशत तथा आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में चार प्रतिशत के दायरे में रहते हुए दिखाई दे सकेगी।

हाल में 12 दिसम्बर को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर बीते महीने नवम्बर में 5.48 प्रतिशत रही। इससे पहले अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.21 प्रतिशत थी। इसी प्रकार नवम्बर में थोक मूल्य मुद्रास्फीति घट कर 1.89 प्रतिशत पर आ गई जो अक्टूबर में 2.36 प्रतिशत थी। यद्यपि महंगाई दर में कमी आई है फिर भी अभी यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के महंगाई के निर्धारित दायरे से अधिक है।

गौरतलब है कि 11 दिसम्बर को आरबीआई के नवनियुक्त 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वे महंगाई नियंत्रण और विकास दर के बीच उपयुक्त संतुलन बनाने की डगर पर आगे बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम काम करने की कोशिश भी करेंगे। गौरतलब है कि इस समय देश में धीमी विकास दर और महंगाई की चुनौती का परिदृश्य उभरता दिखाई दे रहा है।

बीते दिनों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसके पहले अप्रैल-जून की पहली तिमाही में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

इस सुस्त विकास दर के परिदृश्य से प्रभावित हुए बिना हाल में 6 दिसम्बर को आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में विकास दर बढ़ाने के लिए ब्याज दर में कमी नहीं करते हुए महंगाई नियंत्रण को प्राथमिकता दी है।

महंगाई के मद्देनजर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभी बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि जिंस कीमतों में उतार-चढ़ाव और बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम जैसी कई तरह की बाधाएं हैं। आयात शुल्क में वृद्धि और वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बाद घरेलू खाद्य तेल की कीमतों की बदलती दिशा पर भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत है।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने लगातार 11वीं बार ब्याज दर यानी नीतिगत दर (रेपो) में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। रेपो वह ब्याज दर हैङ्क जिस पर कमर्शियल बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से कर्ज लेते हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए इस दर का उपयोग करता है। हालांकि अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के मकसद से आरबीआई ने कैश रिजर्व रेश्यो (सीआरआर) को 4.5 प्रतिशत से घटा कर चार प्रतिशत कर दिया।

इस कदम से बैंकों में 1.16लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। इससे बैंकिंग क्षेत्र में नकदी की स्थिति में सुधार होगा। ज्ञातव्य है कि सीआरआर के तहत कमर्शियल बैंकों को अपनी जमा का एक निर्धारित हिस्सा कैश रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है।

यह बात भी मह'वपूर्ण है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आरबीआई ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7.2 प्रतिशत से घटा कर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई के अनुमान को भी 4.5 प्रतिशत बढ़ा कर 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिसम्बर,2024 की मौद्रिक नीति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि निकट भविष्य में, कुछ नरमी के बावजूद, खाद्य कीमतों पर दबाव बने रहने से चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मुख्य महंगाई के ऊंचे स्तर पर बने रहने की संभावना है। उन्होंने कहा था कि महंगाई के मद्देनजर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभी बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि जिंस कीमतों में उतार-चढ़ाव और बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम जैसी कई तरह की बाधाएं हैं। आयात शुल्क में वृद्धि और वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बाद घरेलू खाद्य तेल की कीमतों की बदलती दिशा पर भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत है।

दास ने कहा था कि रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन के अनुमान से चावल और तुअर दाल की बढ़ी हुई कीमतों में राहत मिलेगी। सब्जियों की कीमतों में भी सुधार की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आगे चल कर, खाद्य मुद्र-ास्फीति के दबाव को कम करने के लिए एक अच्छा रबी सीजन महत्वपूर्ण होगा।

प्रारंभिक संकेत पर्याप्त मिट्टी की नमी और जलाशय के स्तर की ओर इशारा करते हैं, जो रबी की बुवाई के लिए अनुकूल हैं। ऐसे में चालू वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में विकास दर बढ़ने की उम्मीद है। निस्संदेह आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत महंगाई नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना सही कदम है। वस्तुतः पिछले दो महीनों अक्टूबर-नवम्बर,2024 में महंगाई दर के बढ़ने की स्थिति आश्चर्यचकित करने वाली रही है।

किताब लहराने और ऐतिहासिक पुरुषों के प्रतीक वाद पर बहस करने से काम नही चलने वाला

वास्तव में सावरकर धर्म के आधार पर भेद भाव करने वाले समता भूलक नागरिकता के विरोधी है। राहुल गांधी ने संविधान के विषय में उनके विचारों को उद्धृत करके सही काम हो किया है। वास्तव में सावरकर हिंदू राष्ट्र चाहते थे। और उनके हिन्दू राष्ट्र के लिए मनुस्मृति एक संवैधानिक ग्रंथ की तरह से काम करने वाली किताब थी। सावरकर की हिन्दुत्व की विचारधारा मौजूदा संविधान के एकदम विपरीत है। वे मानते थे हिन्दुत्व एक धर्म नहीं विचारधारा है जिसके अनुसार इस देश का भरोसेमंद नागरिक वही हो सकता है जिसके लिए भारत न सिर्फ पितृभूमि हो बल्कि पुण्य भूमि भी हो। यानी भारत न सिर्फ पुरखों की भूमि है बल्कि वह उनके धर्मों की उद्गम स्थली भी है।

ऐसे में इस्लाम और ईसाइयत को मानने वाले लोग भारत के वास्तविक नागरिक नहीं हो सकते हैं जबकि हमारा संविधान टेरिटोरियल नेशनलिटी को मानता है।

यानी इस भू-भाग पर जो भी रह रहा है वह बिना धर्म, जाति और भाषा के भेद भाव के इस देश का नागरिक हो सकता है। उनके हिन्दू राष्ट्र के इसी विस्तार के प्रति डॉ. आंबेडकर ने भी आगाह किया था और कहा था कि वह भारत के लिए बहुत बुरा दिन होगा जिस दिन यह हिंदू राष्ट्र बनेगा। नागरिकता को यह अवधारणा - भारत की महान समन्वयवादी परंपरा की विरासत है। महात्मा गांधी इसकी व्याख्या करते हुए कहते थे- भारत के ज्यादातर मुसलमान और ईसाई तो पहले हिन्दू थे। वे धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्मों में गए हैं लेकिन वे इससे यहां की नागरिकता से वंचित नहीं हो जाते। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि - जिस तरह मेरा बेटा हरिलाल

मुसलमान हो गया तो क्या वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। उनका उत्तर था कि वह नागारिक तो यहीं का रहेगा भले ही उसने दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि-वास्तव में इस देश में न तो मुसलमान जाति व्यवस्था से परे है उन्होंने भले ही धर्म बदल लिया हो।

इसी आधार पर कहा जा सकता है कि-दलित बौद्धों को बाद में आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ जो कि अंबेडकर

द्वारा धर्म परिवर्तन के बाद छिन गया था। दलित मुस्लिम और दलित ईसाई आज भी उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन अगर जाति जनगणना की मांग कर रहा है तो वह पिछले दरवाजे से ईसाइयों और मुसलमानों को आरक्षण देकर देश को विभाजित करने के लिए नहीं कर रहा है। वह वास्तव में भारत को जाति व्यवस्था को बदलने को एक व्यापक योजना के तहत ऐसा हो रहा है।

चिंताएं इस लिए बढ़ जाएंगी कि संविधान चलाने वाले लोगों के पास गान और नैतिकता का वह स्तर नहीं है जिसकी अपेक्षा संविधान करता है। मौजूदा बहस में सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई है कि वह अक्सर आरोपों में फंसकर रह गई है। जब बहस विचारों पर करनी होती है तो वह व्यक्तियों पर बहस करने लगती थी और जब इतिहास पर बहस करनी होती है तो वह मिथकों को आगे कर देती दिक्कत तब हुई जब समाधान पर सावरकर के विचार को लेकर बहस हुई। दरअसल हमारे राजनेताओं के पास वह विवेक और कौशल ही नहीं है कि वे विचार और व्यक्ति को अलग कर सकें। सावरकर के जीवन का उत्तरार्ध और पूर्वार्द्ध को अलग कर सकें। सावरकर के जीवन का पूर्वार्द्ध बलिदानी है लेकिन उनके जीवन का उत्तरार्द्ध समझौतापरक और एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए किसी काम का नहीं है। जो लोग भारत की जाति व्यवस्था के अस्तित्व को पहले नकारते हैं फिर उनका वोट के लिए इस्तेमाल करते है वे 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए डॉ. भीमराव आंबेडकर के उस भाषण को भूल जाते है जिसमें न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक बराबरी के माध्यम से सामाजिक न्याय के लिए चिंता जताई थी यह भी कहा था कि - भारत की गुलामी भारत की गुलामी की बजह उसकी जाति व्यवस्था रही है। उन्होंने इतिहास के तमाम हमलों का जिक्र करते हुए यह आशंका प्रकट की थी कि क्या भारत फि से गुलाम हो सकता है।

अगर भारत में जातिगत विभेद कायम रहा तो ऐसा होने की आशंका है क्योंकि अतीत में इसी व्यवस्था में भारत को कमजोर किया था। इसलिए भारत की एकता और अखंडता के लिए जो चीज जरुरी है वह है जाति विभेद का समूल नाश। वास्तव में व्यक्तियों पर आरोप लगाने या उनको प्रशंसा में अपनी बात को केंद्रित करने से विचार पीछे छूट जाते हैं।

संविधान के बहाने व्यक्तियों को आगे करने की राजनीति इन्हीं सीमाओं में कैद हो जाती है। इस कैद से निकल कर द्रमुक के नेता ए. रजा ने जो बात कही वह संविधान के छह बुनियादी तत्वों को स्पष्ट करती है। उनका कहना था किल भाजपा सरकार ने जिन छः तत्वों को नष्ट किया है वे हैं- लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का राज, समता, संघवाद और न्यायिक स्वायत्तता । हालांकि पिछले लोक सभा चुनाव में संविधान के मूल-चारित्र की हिफाजत को मुद्दा बनाकर विपक्षी दलों ने अच्छा काम किया और उसका परिणाम है कि संविधान पर निरंतर एक दूसरे को राजनीतिक दल घेरने लगे हैं। लेकिन बहस दूर तक जानी चाहिए। केवल किताब लहराने और ऐतिहासिक-पुरुषों के प्रतीकवाद पर बहस करने से काम नहीं चलने वाला है।

चीन-भारत की मित्रता आकाश-कुसुम जैसा

शी जैसे कट्टर निरंकुश नेता का इतने भव्य एवं महत्वाकांक्षी स्वप्न को भुला देना नामुमकिन है। चीन को केवल महाशक्ति बनाना ही नहीं, बल्कि अमेरिका को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने और चीनी मूल्यों पर आधारित नई विश्व व्यवस्था कायम करने जैसे लक्ष्यों को साधने के लिए वह कोई कोर-कसर नहीं छोड़ने वाले। हालांकि उनकी यह राह आसान नहीं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी चीन की इस राह में कांटे बिछाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। यह कोई संयोग नहीं है कि चीन ने भारत समेत जिन एशियाई देशों के साथ स्थलीय और समुद्री सीमाओं से जुड़े विवाद नहीं निपटाए, उनकी अमेरिका के साथ गलबहियां बढ़ी हैं। असल में चीन को संतुलित करने की दृष्टि से ही इन देशों का झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ा है, जिससे चीन और चिढ़ता है।

चीन यह चाहता है कि सीमाओं पर दबाव घटाने के बदले पड़ोसी देश अमेरिका से किनारा करें या अमेरिका के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके लिए मुश्किलें पैदा न करें। इसका अर्थ है कि पड़ोसियों को अपनी विदेश नीति स्वतंत्रता और सामरिक स्वायत्तता को सीमित करना होगा और चीनी प्रभुत्व वाली क्षेत्रीय व्यवस्था को स्वीकार करना होगा। इस प्रकार की शर्त किसी भी स्वाभिमानी देश विशेषकर भारत जैसी उभरती महाशक्ति को कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती।

पांच वर्षों के अंतराल के बाद भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच उच्चस्तरीय वार्ता के बाद द्विपक्षीय संबंधों में नरमी के संकेत मिले। इस वार्ता में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी शामिल हुए। वार्ता की यह पहल पूर्वी लद्दाख और अक्साई चिन सीमा पर 2020 से चले आ रहे सैन्य टकराव को सुलझाने के पश्चात आरंभ की गई है। उस समझौते के तहत चीन ने विवादित क्षेत्रों से अपनी सेना को पीछे हटाया है, जहां उसने भारतीय सेना को गश्त करने से रोका था। सैन्य निकासी के अलावा चीन ने आश्वासन दिया है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के ह्यमूल हितों और प्रमुख सरोकारों को समझते हुए और ईमानदारी एवं सद्भावना के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार हैं। कूटनीतिक सरगर्मियों के मद्देजनर अहम सवाल यही है कि क्या चीन का भारत के प्रति वाकई कोई हृदय परिवर्तन हुआ है और अगर ऐसा हुआ है तो इसका कारण क्या है? बीते 12 वर्षों से चीन पर राज करते हुए तानाशाह राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मंशा पर ध्यान दें तो यह असंभव है कि उन्होंने एशिया और विश्व में चीन के वर्चस्व और विस्तारवाद का सपना रातोंरात त्याग दिया है। प्रमुख देश कूटनीति नामक उनकी अवधारणा के अनुसार चीन कभी भी अपने ह्यवैध अधिकारों और हितों को नहीं छोड़ेगा और पड़ोसी देशों के साथ विवादों में अपनी शक्ति एवं श्रेष्ठता के बलबूते हावी रहेगा। भारत के अलावा एक दर्जन से अधिक देशों के साथ चीन के अनसुलझे क्षत्रीय विवाद हैं और इन सभी के प्रति शी के शासन में चीन ने दबंग व्यवहार अपनाकर धौंस देना जारी रखा है। ग्रे जोन और सलामी स्लाइसिंग रणनीतियों का उपयोग करते हुए चीन ने पड़ोसियों पर सैन्य एवं आर्थिक दबाव डालकर यही चेष्टा की है कि कमजोर देशों पर चीन की इच्छा थोपी जाए। उनके अतिराष्ट्रवादी ह्यचीनी स्वप्न का लक्ष्य एशिया में उस पुराने साम्राज्यवादी युग को पुनः स्थापित करना है, जहां चीन का कथित तौर पर प्रभुत्व था और पड़ोसियों को बीजिंग में सम्राट के सामने झुककर प्रणाम करना पड़ता था। अजीत डोभाल और वांग यी के बीच हालिया वार्ता विवादित ह्यसीमा प्रश्नह्ल पर विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक है और यह सिलसिला बिना किसी अंतिम सहमति के वर्ष 2003 से निरंतर जारी है। इसके अतिरिक्त, ह्यसीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्रह्ल की 2012 से अब तक 32 बैठकें हो चुकी हैं।

इनमें भाग लेने वाले भारतीय वाताकारों और राजनयिकों का मानना है कि चीन इस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त करने का इच्छुक नहीं दिखता और वह भारत की ओर से प्रस्तुत किए गए मानचित्रों की बारीकियों में भी नहीं जाता। चीन लगातार थकाऊ वाताओं के माध्यम से संघर्ष को प्रबंधित करने का प्रयास करता है, परंतु अपने क्षेत्रीय दावों को नहीं छोड़ता। वर्ष 2020 में गलवन घाटी में मुठभेड़ और उसके बाद करीब साठ हजार सैनिकों एवं भारी-भरकम हथियारों की तैनाती चीन को खासी महंगी पड़ी। भारतीय सेना ने जिस मुस्तैदी के साथ जवाबी कार्रवाई की और अतिरिक्त चीनी घुसपैठ के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए, उसने शी की चिंताएं बढ़ा दी थीं।

अमेरिका के साथ भारत की सामरिक साझेदारी भी बीते कुछ वर्षों के दौरान जिस प्रकार मजबूत होती गई, उसने भी चीन के माथे पर बल डालने का काम किया। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सत्ता में वापसी और उनके द्वारा छेड़े जाने वाले संभावित व्यापार युद्ध और सैन्य चुनौती भी शी की आशंका का कारण है-इसलिए और भी, क्योंकि चीन की आर्थिक वृद्धि सुस्त पड़ गई है। ऐसे में, भारत के प्रति नरम रवैये का प्रदर्शन कर शी चीन के लिए थोड़े समय के लिए सामरिक राहत की खोज में होंगे।दिपसांग और देमचोक से चीनी सेना की वापसी शी की नाकामी का परिचायक है, लेकिन यह ध्यान रहे कि उनके जैसे महत्वाकांक्षी तानाशाह आसानी से हार नहीं मानते। चीन भारत को झुकाने का इरादा तब तक मन में रखेगा, जब तक वह आश्वस्त न हो जाए कि भारत अमेरिका के संग मिलकर उसकी घेराबंदी करना नहीं छोड़ता।

चूंकि अमेरिका की मित्रता भारत के उत्थान के लिए अनिवार्य है, इसलिए चीन के साथ भारत की अनबन और प्रतिस्पर्धा में कमी की अपेक्षा अवास्तविक है। भारत-चीन वार्ता के दौर सीमा पर उल्लंघित नियमों को बहाल करने में कमोबेश मददगार हो सकते है, लेकिन भू-राजनीतिक स्तर पर मैत्रीपूर्ण संबंध की संभावना दूर की कौड़ी है। जब तक चीन भारत के महाशक्ति बनने में अड़चनें डालता रहेगा, उससे दोस्ती की अपेक्षा काल्पनिक बनी रहेगी। कूटनीतिक बैठकों के समानांतर भारत को अपनी सैन्य तैयारियों और क्षमताओं को उन्नत करते हुए चीन से सतर्क रहने की नीति पर ही चलना होगा।

आधुनिक तकनीकी बदर में सचेत रहने की अनिवार्यता

एन सी आर बी की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में साइबर क्राइम के 65893 मामले दर्ज किये गए हैं। साल-2021 में 52974 मामले दर्ज किये गए थे। इस तरह एक साल के दौरान साइबर अपराध में 24.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज गई है। इनमें भी करीब 65 फीसदी मामले धोखाधड़ी के ही हैं। यानी 65893 मामलों में 42790 धोखाधड़ी के मामले हैं जब कि 3648 मामले जबरन उगाही के हैं। 2023 एवं 2024 में भी स्थिति कोई संतोषजनक नहीं, बल्कि ये छलांग मारकर तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत में उभरते साइबर सुरक्षा-चुनौतियों के लिए निरंतर विचार और तत्परता को आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा में विशेषज्ञता रखने वाली संस्थाओं और सरकारी आपस के साथ साझेदारी करने से नये विचार और विशेष विशेषज्ञता सामने आ सकती है। यह समय साइबर क्राइम न केवल व्यवसायों और व्यक्तियों की सुरक्षा करेगा बल्कि भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास में योगदान देगा। भारत भर में एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है। जिसमें साइबर धोखाधड़ी ग्रामीण इलाकों में सीमित डिजिटल जानकारी रखने वाले लोगों से लेकर शहरी इलाको में तकनीकी रूप से दक्ष लोगों तक को अंधाधुंध तरीके से निशाना बना रही है। भारत आज भले हो डिजिटल विकास के छोर पर बैठा है। लेकिन कंपनियों को सुनिश्चित करना है कि वे डिजिटल विकास से आने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है भी या नहीं। ऐसा करने का एक मात्र तरीका यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी एवं बोर्ड के एजेंडे में साइबर सुरक्षा सर्वोपरि हो, ताकि डिजिटल संग्रह को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, भले मानने योग्य है कि - जागरूकता की कमी है, लेकिन हैकर सब कुछ इस तरीके से करते हैं कि आपकी जागरूकता धरी की धरी रह जाती है। इसमें सुरक्षा उपायों की कमी महसूस होती है। सरकार एवं प्रशासन अनेक स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक इलाज जागरुकता को कमी प्रतीत होती है। साइबर अपराध एक सामान्य शब्द है। जो कंप्यूटर, नेटवर्क, या डिजिटल उपकरणों के किसी अन्य सेट का उपयोग करके की जाने वाले असंख्य आपराधिक गतिविधियों का वर्णन करता है।

साइबर अपराध को साइबर अपराधियों द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियों की विशाल श्रृंखला के अंतर्गत माना जाता है। इनमें हैकिंग, फिशिंग, पहचान को चोरी, रैनसम वेयर मॉलवेयर हमले कई अन्य शामिल हैं। साइबर अपराध को पहुँच कोई भौतिक सीमा नहीं जानती। अपराधी पीड़ित और तकनीकी अवसंरचना दुनिया भर में फैली हुई है। व्यक्तिगत और उद्यम स्तर पर सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए प्रौद्योगिकी के लगातार उपयोग के साथ साइबर अपराध कई रूप लेता है और विकसित होता रहता है। बदले में साइबर अपराधों की प्रभावी जाँच, मुकदमा चलाने और उन्हें रोकने की क्षमता कई गतिशील चुनौतियों के साथ सतत लड़ाई है। साइबर अपराध व्यक्तियों व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं के लिए एक गंभीर खतरा है और उसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान प्रतिष्ठा को नुकसान और रिकॉर्ड से समझौता हो सकता है।

वर्तमान तकनीकी युग तकनीकी एवं साइबर विकास का है। प्रौद्योगिक क्रांतिकारी है। अनेक कार्य तकनीकी सहायता से सुगम हो चुके हैं। सभी कार्य आसानी से घर बैठे संपन्न हो जाया करते हैं। बाजार को पहुँच भी घर तक सुनिश्चित हो चुका है। लेकिन इसी क्रम में अपराधियों की पहुंच भी सोधे घर तक हो गयी है। पलक झपकते ही अपराधी अपने संसूबों को अंजाम दे गलत हैं। भारत जहां विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है परन्तु मेहनत की कमाई उड़ा रहे हैं। तकनीक में तेजी से बढ़ रहे अपराध ने लोगों को निजी जानकारी और सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। साइबर के कई अपराध हैं- चाहे वह जानकारी को चोरी करना हो हैकिंग हो, फिशिंग हो, वायरस, फैलाना हो, सॉफ्टवेयर पाइरेसी हो, फर्जी बैंक कॉल हो, सोशल नेट वर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना एवं साइबर बुकिंग इत्यादि हो। इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि चिंता जनक है। जिस देश का प्रधान मंत्री स्वयं मनकी बात' जैसे देशव्यापी कार्य कम के माध्यम से चिंता व्यक्त कर इससे बचने केलिए आग्रह कर रहा हो, सोचिए यह कितनी बड़ी समस्या बनती जा रही है। प्रधान मंत्रो का देशवासियों से आग्रह है कि जब कोई काल आए लो घबराने को आवश्यकता नहीं है। बल्कि रुको, सोचो. फिर एक्शन लो। इस कम को अपनाने की आवश्यकता है। जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ती है। और अधिक से अधिक लोग मानक संचालन के लिए डिजिटल उपकरणों और नेटवर्क पर निर्भर होते हैं। साइबर अपराध का खतरा बढ़ता जा रहा है। इनसे बचाव के लिए कदम उठाना पहले से अधिक महत्व पूर्वी हो गया है। साइबर अपराधों से जुड़ी कुल लागत और जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए रोकथाम और प्रौद्योगिकियों को लगातार लागू करने, निगरानी करने और अपग्रेड करने की आवश्यकता भी बढ़ रही है। विदेशी विरोधियों, आतंकवादियों और रोज गर्ग के घोटाले बाजों के बीच साइबर हमले ज्यादा चालाक और ज्यादा परिष्कृत होते जा रहे हैं।

दान करने की प्रथा अति प्राचीन और सामान्य प्रक्रिया

भारत में हिंदू सनातन संस्कृति के संस्कारों में दान दक्षिणा की प्रथा का अलग ही महत्व है। भारत में विभिन्न त्यौहारों एवं महापुरुषों के जन्म दिवस पर मठों मंदिरों, गुरुद्वारों एवं अन्य पूजा स्थलों पर समाज के सम्पन्न नागरिकों द्वारा दान करने की प्रथा अति प्राचीन एवं सामान्य प्रक्रिया है। गरीब वर्ग की मदद करना ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा माना जाता है। समाज में आपस में मिल बांटकर खाने पीने की प्रथा भी भारत में ही पाई जाती है और यह प्रथा भारतीय समाज में बहुत आम है। परिवार में आई किसी भी खुशी की घटना को समाज में विभिन्न वर्गों के बीच आपस में बांटने की प्रथा भी भारत में ही पाई जाती है। इस उपलक्ष में कई बार तो बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं। जैसे जन्म दिवस मनाना, परिवार में शादी के समारोह के पश्चात समाज में नाते रिश्तेदारों, दोस्तों एवं मिलने वालों को विशेष आयोजनों में आमंत्रित करना, आदि बहुत ही सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत के विभिन्न मठों, मंदिरों, गुरुद्वारों एवं अन्य पूजा स्थलों पर प्रतिदिन 10 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्रसादी के रूप में भोजन वितरित किया जाता है।

साथ ही, पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है, जिसमें निवासरत नागरिक, चाहे वह कितना भी गरीब से गरीब क्यों न हो, अपनी कमाई में से कुछ राशि का दान तो जरूर करता है। भारतीय शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि हिंदू सनातन संस्कृति के अनुरूप, महर्षि दधीच ने तो, देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से, अपने शरीर को ही दान में दे दिया था, जिसे इतिहास में उच्चत्तम बलिदान की संज्ञा भी दी जाती है।

आज के युग में जब अर्थ को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है, तब अधिक से अधिक धनराशि का दान करना ही शुभ कार्य माना जा रहा है। इस दृष्टि से वैश्विक स्तर पर नजर डालने पर ध्यान में आता है

कि दुनिया में सबसे बड़े दानदाता के रूप में आज भारत के टाटा उद्योग समूह के श्री रतन टाटा का नाम सबसे ऊपर उभर कर सामने आता है। इस सूची में टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का नाम भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में 8.29 लाख करोड़ रुपए की राशि का महादान किया था।

इसी प्रकार, रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वर्ष 2021 तक 8.59 लाख करोड़ रुपए की राशि का महादान किया था। आप अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब वर्ग की सहायतार्थ दान में दे देते थे। श्री रतन टाटा केवल भारत स्थित संस्थानों को ही दान नहीं देते थे बल्कि वैश्विक स्तर पर समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहे संस्थानों को भी दान की राशि उपलब्ध कराते थे। आपने वर्ष 2008 के महामंदी के दौरान अमेरिका स्थित कार्नेल विश्वविद्यालय को 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का दान प्रदान किया था।

रतन टाटा ने आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जे. एन. टाटा एंडाउमेंट, सर रतन टाटा स्कॉलर्शिप एवं टाटा स्कॉलर्शिप की स्थापना कर दी थी। रतन टाटा चूंकि अपनी कमाई का बहुत बड़ा भाग दान में दे देते थे, अतः उनका नाम कभी भी अमीरों की सूची में बहुत ऊपर उठकर नहीं आ पाया। इस सूची में आप सदैव नीचे ही बने रहे। श्री रतन टाटा जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी बड़ी राशि का दान किया था कि आज विश्व के 2766 अरबपतियों के पास इतनी सम्पत्ति भी नहीं है।

यूं तो टाटा समूह ने भारत राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु कोरोना महामारी के खंडकाल में रतन टाटा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जिस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस समय रतन टाटा ने न केवल भारत बल्कि विश्व के कई अन्य देशों को भी आर्थिक सहायता के साथ साथ वेंटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, मास्क और दस्ताने आदि सामग्री उपलब्ध कराई। रतन टाटा के निर्देशन में टाटा समूह ने इस खंडकाल में 1000 से अधिक वेंटिलेटर और रेस्पिरेटर, 4 लाख पीपीई किट, 35 लाख मास्क और दास्ताने और 3.50 लाख परीक्षण किट चीन, दक्षिणी कोरिया आदि देशों से भी आयात के भारत में उपलब्ध कराए थे।

रतन टाटा के पूर्वज पारसी समुदाय से थे और ईरान से आकर भारत में रच बस गए थे। रतन टाटा ने न केवल भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति के संस्कारों को अपने जीवन में उतारा, बल्कि इन संस्कारों का अपने पूरे जीवनकाल में अक्षरशः अनुपालन भी किया। इन्हीं संस्कारों के चलते रतन टाटा को आज पूरे विश्व में सबसे बड़े दानदाता के रूप में जाना जा रहा है।

टाटा समूह का वर्णन तो यहां केवल उदाहरण के रूप में किया जा रहा है। अन्यथा, भारत में ऐसे कई औद्योगिक घराने हैं जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को ही ट्रस्ट के माध्यम से समाज के उत्थान एवं समाज की भलाई के लिए दान में दे दिया है। प्राचीन भारत में यह कार्य राजा महाराजाओं द्वारा किया जाता रहा हैं। हिंदू सनातन संस्कृति के विभिन्न शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि ईश्वर ने जिसको सम्पन्न बनाया है, उसे समाज में गरीब वर्ग की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। यह सहायता गरीब वर्ग को सीधे ही उपलब्ध कराई जा सकती है अथवा ट्रस्ट की स्थापना कर भी गरीब वर्ग की मदद की जा सकती है। वर्तमान में तो निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर - कोरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी) के सम्बंध में कानून की बना दिया गया है। जिन कम्पनियों की सम्पत्ति 500 करोड़ रुपए से अधिक है अथवा जिन कम्पनियों का वार्षिक व्यापार 1000 करोड़ रुपए से अधिक है अथवा जिन कम्पनियों का वार्षिक शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक है, उन्हें इस कानून के अंतर्गत अपने वार्षिक शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत की राशि का उपयोग समाज की भलाई के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं पर खर्च करना आवश्यक होता है। इन विभिन्न मदों पर खर्च की जाने वाली राशि का प्रतिवर्ष अंकेक्षण भी कराना होता है, ताकि यह जानकारी प्राप्त की जा सके राशि का सदुपयोग समाज की भलाई के लिए किया गया है एवं इस राशि का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं हुआ है।

भारत में गरीब वर्ग/परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में समाज में सम्पन्न वर्ग द्वारा किए जाने वाले दान आदि की राशि से भी बहुत मदद मिलती है। निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) योजना के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ भी समाज के गरीब वर्ग को ही मिलता है। अतः विश्व में शायद भारत ही एक ऐसा देश है जहां सरकार एवं समाज मिलकर गरीब वर्ग की भलाई हेतु कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए ही अब यह कहा जा रहा है कि हिंदू सनातन संस्कृति का विस्तार यदि वैश्विक स्तर पर होता है तो, इससे पूरे विश्व का ही कल्याण हो सकता है एवं बहुत सम्भव है कि वैश्विक स्तर पर गरीबी का नाश होकर चहुं ओर खुशहाली फैलती दिखाई दे।

जनसंख्या नियंत्रण और प्रतिनिधित्व की समानता का संतुलन चुनौतीपूर्ण

1972 के बाद पचास वर्षों से अधिक समय से पूर्ण परिसीमन नहीं हुआ है। आज देश की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो गई है, पर सांसदों और विधायकों की संख्या नहीं बढ़ी। इससे सांसद और विधायक अत्यधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक सांसद औसतन 25 लाख और विधायक पांच-सात लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि इंग्लैंड के सांसद एक लाख और अमेरिका के सात लाख लोगों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः आगामी परिसीमन आयोग द्वारा सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाने का प्रतिवेदन जरूरी है। जनप्रतिनिधियों की संख्या न बढ़ने से दूसरी समस्या यह है कि प्रतिनिधित्व की समानता का सिद्धांत ध्वस्त हो गया है। ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद के मत का मूल्य वही है, जो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद का। यदि केवल जनसंख्या को परिसीमन और सीटों के आवंटन का आधार बनाया जाएगा, तो वे राज्य दंडित होंगे, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है।

आगामी परिसीमन में अनुमानतः कर्नाटक में 8, तेलंगाना और आंध्र में 3-3, तमिलनाडु में 2 सीटें बढ़ेंगी, जबकि केरल में एक लोकसभा सीट घट सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में 18, राजस्थान में 19, महाराष्ट्र में 20, बिहार में 30 और उत्तर प्रदेश में 48 सीटें बढ़ सकती हैं। आगामी परिसीमन में जनसंख्या नियंत्रण और ह्यप्रतिनिधित्व की समानताह्ल में संतुलन चुनौतीपूर्ण होगा। इस पर आश्चर्य नहीं कि दक्षिण के राज्य परिसीमन को लेकर आशंका जताने लगे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद को सूचित किया था कि लोकसभा चुनाव बाद जनगणना और परिसीमन कराया जाएगा।

देश में चुनावों पर चर्चा होती है, लेकिन चुनाव इकाइयों अर्थात निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर चर्चा नहीं होती। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन कराने का प्रविधान है। संविधान (अनु.327) संसद को परिसीमन का अधिकार देता है, जिसमें दो बड़े मुद्दे हैं-प्रथम, लोकसभा और विधानसभाओं में कितने-कितने जनप्रतिनिधि होने चाहिए? दूसरा, लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं, उनके आकार-प्रकार में क्या कोई बदलाव जरूरी है? संविधान संसद को अधिकार देता है कि वह उपरोक्त दोनों मुद्दों के समाधान हेतु अभिकरण बनाए और परिसीमन प्रक्रिया निर्धारित करे। प्रथम लोकसभा और विधानसभा चुनावों हेतु परिसीमन राष्ट्रपति कार्यालय ने किया। संसद ने 1952 में प्रथम परिसीमन

आयोग का गठन किया, जिसने 1957 के चुनावों हेतु परिसीमन किया। उसके बाद 1962 और 1972 में द्वितीय और तृतीय परिसीमन आयोगों ने 1971 एवं 1972 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर 42वें संविधान संशोधन द्वारा अगले 25 वर्ष तक परिसीमन पर रोक लगा दी। फलतः 1981 और 1991 में परिसीमन नहीं हो सका। संसद द्वारा 2002 में चतुर्थ परिसीमन आयोग का गठन हुआ, लेकिन 84वें संविधान संशोधन (2001) द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाने पर 2026 के बाद होने वाली जनगणना तक इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि 2026 तक देश में जन्मदर और मृत्युदर बराबर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फलतः चतुर्थ परिसीमन आयोग केवल आंशिक परिसीमन कर सका।

परिसीमन में लोकसभा की सीटें बढ़ना तय हैं। मोदी सरकार ने दूरदर्शिता से नई संसद का निर्माण कराया, जिसमें 888 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन राज्यों ने इस पर अभी ध्यान नहीं दिया है। लोकसभा में करीब डेढ़-दो सौ सीटें बढ़ना तय है। युवाओं को इसका लाभ लेना चाहिए। पीएम मोदी ने युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान भी किया है। नारीशक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं हेतु लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या पर 181 महिला सीटें आरक्षित होंगी और यदि परिसीमन से न्यूनतम 150 लोकसभा सीटें भी बढ़ती हैं, तो लोकसभा में 231 महिला सीटें आरक्षित होंगी, जिसका लाभ महिलाओं को मिलेगा। अनुसूचित जाति-एससी और अनुसूचित जनजाति-एसटी की आरक्षित सीटों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि अनु. 330(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों में एससी और एसटी के लिए उसी अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी, जो अनुपात उनका राज्य की आबादी में होगा। जब 2006 में आंशिक परिसीमन हुआ था, तब लोकसभा सीटों के बढ़ने पर तो प्रतिबंध था, पर एससी की आरक्षित सीटें 79 से बढ़कर 84 और एसटी की सीटें 41 से बढ़ कर 47 हो गई थीं। अगले परिसीमन में यह संख्या और बढ़ेगी। आगामी परिसीमन आयोग को या तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या तय कर उन्हें राज्यों को आवंटित करने का फामूर्ला बनाना होगा या यह तय करना होगा कि 2026 में भारत की अनुमानित जनसंख्या एक अरब 42 करोड़ में कोई सांसद अधिकतम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके आधार पर ही लोकसभा सीटों की संख्या निर्धारित होगी। संसद को परिसीमन आयोग अधिनियम 2026 में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आयोग संवैधानिक प्रविधानों का अनुपालन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत कर उनको कुछ अतिरिक्त लोकसभा सीटें आवंटित करे।

इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि परिसीमन में अपने यहां लोकसभा सीटों की संख्या में कटौती की आशंका के कारण दक्षिण के कुछ राज्य जनसंख्या बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। पूर्ववर्ती परिसीमन आयोगों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किस फामूर्ले के आधार पर परिसीमन किया। आयोग में प्रत्येक राज्य से पांच सांसद और विधायक क्रमशः लोकसभा और विधानसभाओं के स्पीकर द्वारा नामित किए जाते हैं, पर वे भी परिसीमन प्रक्रिया की बारीकियों को नहीं जानते या जानना नहीं चाहते। उन्हें अपना निर्वाचन क्षेत्र बचाने की ही चिंता होती है।

अतः अगले परिसीमन आयोग को कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के साथ ही विषय विशेषज्ञों को भी परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित करना होगा। इससे परिसीमन में जानबूझकर या अनजाने में होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है। परिसीमन में पारदर्शिता और परामर्श इसलिए और जरूरी है, क्योंकि अनु.329 परिसीमन आयोग के निर्णयों में न्यायपालिका हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता।

घूँघट की बगावत

22 दिसम्बर 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

शून्य में विलीन हुए जाकिर हुसैन

दुनियाभर में शास्त्रीय संगीत में भारत को अलग पहचान दिलाने वाले उस्ताद और मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं रहे। 73 साल की उम्र में हुसैन ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आखिरी सांस ली। उनके निधन से आज भारतीय संगीत की लय थम गई, सुर मौन हो गए, भाव शून्य हो गए। मौसिकी की दुनिया में हुसैन के तबले की थाप एक अलहदा पहचान रखती है, वे दुनिया भर के अनगिनत संगीत प्रेमियों द्वारा संजोई गई एक असाधारण विरासत छोड़ गए हैं, जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक बना रहेगा। भारतीय तबले की गौरवशाली परंपरा की सुगंध विश्व भर में प्रसारित करने वाले हुसैन के अनंत में विलीन होने से गहन सन्नाटा छा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत एवं तबला वादन का दुनिया में विशिष्ट स्थान है, क्योंकि यह सत्यं, शिवं और सौन्दर्य की युगपत उपासना की सिद्ध एवं चमत्कारी अभिव्यक्ति है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में क्रांति का शंखनाद किया। उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ, जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्ला रक्खा के बेटे थे। हुसैन का बचपन मुंबई में ही बीता। 12 साल की उम्र से ही जाकिर हुसैन ने संगीत की दुनिया में अपने तबले की आवाज को बिखेरना शुरू कर दिया था। प्रारंभिक शिक्षा और कॉलेज के बाद हुसैन ने कला के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया। 1973 में उनका पहला एलबम लिविंग इन द मैटेरियल वर्ल्ड आया था। उसके बाद तो जैसे जाकिर हुसैन ने ठान लिया कि अपने तबले की आवाज को दुनिया भर में बिखेरेंगे। 1979 से लेकर अब तक जाकिर हुसैन विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समारोहों और एलबमों में अपने तबले का दम दिखाते रहे। जाकिर हुसैन भारत में तो बहुत ही प्रसिद्ध थे साथ ही साथ विश्व के विभिन्न हिस्सों में भी समान रूप से लोकप्रिय थे। वे भारतीय संगीत जगत का एक उज्ज्वल नक्षत्र थे। वे पारम्परिक कौशल, रचनात्मकता एवं संवेदनशीलता से युक्त तबला वादन में कल्पनाशील विस्तार, गहन अलौकिकता और अचूक कलात्मक संयम एवं वैभव के लिये विख्यात थे। वे अपनी कला के अकेले महारथि थे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत एवं कला को लोकरंजन का साधन बनाने के लिये क्लिष्टता को दूर कर उसे सुगम बनाया। ईश्वर को आलोकपुंज मानते हुए उससे एकाकार होकर अपनी कला को प्रस्तुति देते हुए हुसैन ऐसा प्रतीत कराते थे, मानो उनका ईश्वर से सीधा साक्षात्कार हो रहा है। यही कारण है कि उनके तबले वादन एवं संगीत साधना से रू-ब-रू होने वाले असंख्य लोग उनकी साधना में गौता लगाते हुए मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनका यह स्थान सर्वोपरि रहा है, जिसे अब कोई पूरा नहीं कर सकता। उनके निधन से तबला वादन संसार की एक पाठशाला आज वीरान हो गई। जाकिर हुसैन यूं तो सम्मान एवं पुरस्कारों से ऊपर थे। फिर भी उन्हें 1988 में जब पद्मश्री का पुरस्कार मिला था तब वह महज 37 वर्ष के थे और इस उम्र में यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे। इसी तरह 2002 में संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उस्ताद जाकिर हुसैन तबले को हमेशा आम लोगों से जोड़ने की कोशिश करते थे। यही वजह थी कि शास्त्रीय विधा में प्रस्तुतियों के दौरान बीच-बीच में वे अपने तबले से कभी डमरू, कभी शंख तो कभी बारिश की बूंदों जैसी अलग-अलग तरह की ध्वनियां निकालकर सुनाते थे। वे कहते थे कि शिवजी के डमरू से कैलाश पर्वत से जो शब्द निकले थे, वही शब्द लेकर उन्हें ताल की जुबान में बांधा। हम सब तालवादक, तालयोगी या तालसेवक उन्हीं शब्दों को अपने वाद्य पर बजाते हैं।

नशा पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती

नशे के तेजी से बढ़ते शिकंजे से न केवल असामयिक मौतों, लाइलाज बीमारियों का खतरा बढ़ता है, बल्कि समाज में अपराधों का सिलसिला भी तेज हो जाता है। देखने में आया है कि बड़े अपराधों से लेकर चोरी छीनाझपटी की घटनाओं के मूल में नशाखोरी की भूमिका होती है। कई आपराधिक घटनाओं के मूल में उन कालेज जाने वाले छात्रों की भूमिका पायी गई है, जो नशे के लिये पैसा जुटाने के लिये अपराध की अंधी गलियों में उतर जाते हैं। यह जानते हुए भी यह रास्ता उनके जीवन को बबार्दी की राह पर ले जाता है। निश्चित रूप से समाज विज्ञानियों को भी व्यापक अध्ययन करना चाहिए कि क्यों नई पीढ़ी नशे की ओर तेजी से उन्मुख हो रही है। एक समय था कि पंजाब में आतंक फैलाने के खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिये सीमा पार से नशे की बड़ी खेप पंजाब भेजी जाती रही है। चरमपंथियों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिये भी इस षड्यंत्र को सुनियोजित तरीके पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठानों ने अंजाम दिया। हाल के दिनों में बीएसएफ ने पाकिस्तान की सीमा से लगते भारतीय इलाकों में ड्रोन के जरिये नशीले पदार्थों को गिराने की साजिशों पर लगाम लगायी है। निश्चित रूप से पहले कदम के रूप में सीमाओ को नशे की तस्करी से निरापद बनाने की जरूरत है। वहीं हमार सुरक्षा व्यवस्था में शामिल उन काली भेड़ों को भी बेनकाब करने क जरूरत है जो नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रही हैं। साथ ही नष्ट से पीड़ितों को इस दलदल से बाहर निकालने के लिये नशा मुक्ति केंद्री की स्थापना और पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक उपचार देने की भ जरूरत है। निश्चित रूप से नशा पंजाब के लिये बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जिसके रिटलाफ साझा लड़ाई से ही हम कामयाब हो सक हैं। सही मायनों में यह स्थिति इस संवेदनशील सीमांत राज्य के लिन ही चुनौती नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय संकट की भी आहट है। केंद्रीय एजेंसियों व पंजाब के शासन-प्रशासन को मिलकर नशे के समूब नाश के लिये व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है।

> नशे के नश्तर से महिलाओं को मर्मांतक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अब चाहे पति हो या बेटा, नशे की लत लगने से पूरा परिवार ही संकट में आ जाता है। इसमें दो राय नहीं कि जब पंजाब की नारी शक्ति एकजुट होकर इस मुहिम का नेतृत्व करेगी तो पंजाब अपने स्वर्णिम दिनों की ओर लौट सकता है। निश्चित रूप से किसी राज्य या देश की जवानी का नशे के सैलाब में डूबना राष्ट्रीय क्षति ही है।

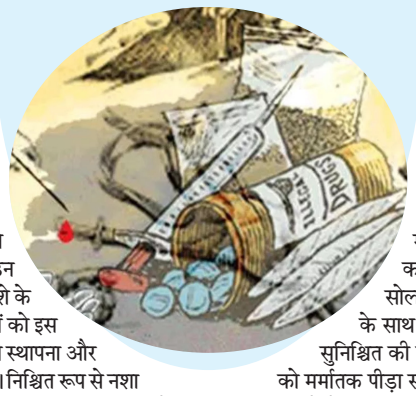

देश में नासूर बनते नशे के खिलाफ अभियान में यदि 114 वर्षीय धावक फौजा सिंह प्रेरक पदयात्रा कर सकते हैं तो ऊजार्वान युवा-बुजुर्ग क्यों नहीं। नशा मुक्त-रंगला पंजाब अभियान के अंतर्गत निकाले गए नशा विरोधी मार्च में मंगलवार को मैराथन धावक फौजा सिंह के साथ ही पंजाब के राज्यपाल अस्सी वर्षीय गुलाब चंद कटारिया की आठ किलोमीटर की पैदल यात्रा सुर्खियों में रही। निश्चित रूप से पंजाब सरकार की पहल अनुकरणीय है। इसमें दो राय नहीं कि कोई भी बड़ा सामाजिक बदलाव का आंदोलन व्यापक जन भागीदारी से ही सिरे चढ़ सकता है। आज पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों में युवा पीढ़ी जिस भयावह तरीके से नशे के दलदल में धंसती जा रही है, वह राष्ट्र के लिये एक गंभीर चुनौती है। जिसका मुकाबला सरकारों के साथ आम आदमी के जुड़ाव से ही संभव है। निश्चित रूप से ऐसी पदयात्रा सिर्फ राजनीतिक निहितार्थों और प्रतीकात्मक रूप से आयोजित नहीं होनी चाहिए। ऐसे अभियान को आंदोलन का रूप देकर इस तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाना चाहिए। साथ ही इस तरह के अभियानों से हासिल उपलब्धियों का मूल्यांकन भी जरूरी है। निस्संदेह, औपचारिकताओं के निर्वहन और मीडिया में सुर्खियां बटोरना ऐसे आंदोलन का लक्ष्य तो कदापि नहीं हो सकता। राज्यपाल महोदय का यह कथन सोलह आने सच है कि इस मुद्दे पर बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही महिलाओं की इस आंदोलन में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। निस्संदेह, नशे के नश्तर से महिलाओं को मर्मांतक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अब चाहे पति हो या बेटा, नशे की लत लगने से पूरा परिवार ही संकट में आ जाता है। इसमें दो राय नहीं कि जब पंजाब की नारी शक्ति एकजुट होकर इस मुहिम का नेतृत्व करेगी तो पंजाब अपने स्वर्णिम दिनों की ओर लौट सकता है। निश्चित रूप से किसी राज्य या देश की जवानी का नशे के सैलाब में डूबना राष्ट्रीय क्षति ही है। इसके लिये नशे की आपूर्ति रोकने से लेकर प्रयोग तक पर नियंत्रण की राष्ट्रव्यापी मुहिम की जरूरत है।

महिलाएं और चुनावी रिश्वत: सत्तारूढ़ होते राजनीतिक दल

राजनीतिक दल चुनावी राजनीति के हिसाब से किस तरह से महिलाओं को सॉफ्ट टार्गेट मान रहे हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विभिन्न राज्यों में सत्तारुढ सरकारें अब चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में एक निश्चित रकम भेजने की योजना लाते हैं। और अगर संभव होता है तो एक-दो किस्त भेज देते भी है और फिर महिलाओं से यह वादा भी करते हैं कि अगर वे उनकी पार्टी को चुनाव जिता दें तो फिर से सरकार बनने के बाद राशि को अदा कर देंगे। अब इसे महिला सम्मान योजना का नाम दिया जाये या लाडली बहना योजना का नाम दिया जाय या कोई और नाम दिया जाए लेकिन सही मायनों में यह एक चुनावी रिश्वत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाल ही में दिल्ली को आम आदमी पार्टी सरकार ने भी यही किया विधान सभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद के-जरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर हर महिला के खाते में एक हजार रुपए भेजने की घोषणा की हालांकि वे और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी दोनों भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि- चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे जाने की संभावना बहुत ही कम हो लेकिन उस पर भी तुर्रा यह कि केजरीवाल ने एक तरह से महिलाओं को चुनावी लालच देते हुए यह भी घोषणा कर दी है कि विधान सभा चुनाव जितवा दो तो इसे बढ़ाकर 2100 कर दिया जायेगा । हालांकि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने इस योजना में होने वाले खर्च की राशि को लेकर कई तरह की गंभीर चिंता व्यक्त की हैं। भारतीय राजनीतिक दलों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बनती जा रही हैं। देश के सभी राजनीतिक दलों को यह लगने लगा कि महिला मतदाताओं को लगा चुनावी जीत हासिल की जा सकती है। यह वजह है एक के बाद एक कई राज्यों में राजनीतिक दलों के खास का सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों ने महिलाओं के खाते में सीधे कैश पहुंचा कर सत्ता में फिर से वापसी करने में कामयाबी हासिल कर ली है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना चला कर अपने आपको पूरे राज्य की महिलाओं के लिए भाई और बच्चों के लिए मामा के रूप में स्थापित कर चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान के नक्शे कदम पर चलते हुए हाल ही में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की महायुति गठबंधन सरकार और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने सत्ता में जोरदार वापसी की है। भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में इस तरह की योजनाओं की प्रासंगिकता पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि राजनीतिक दल इसे चुनाव जीतने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने लग गए हैं। चुनावी शोर, चुनावी वादे, और चुनावी जीत की गहमा गहमी के बीच असली मुद्दे कहीं गौण होते नजर आ रहे हैं।

सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह की योजनाएं चुनाव के पहले ही क्यों शुरू की जाती है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि - क्या एक हजार, 1500, 2100 या तीन हजार रुपए शशि से सभी समस्याओं का निदान स्थाई समाधान हो सकता है। वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में फ्री शिक्षा फ्री स्वास्थ्य और फ्री नौकरी होती है लेकिन विडंबना देखिए की सरकारों ने इन मुद्दों पर काम काम करने की बजाय काम चलाऊ हल खोज रखा है।

कानून सभी के लिए समान

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान ही सर्वोपरि होता है, जिसके आधार पर न्याय, समता, समानता जैसे मूल्यों की बुनियाद पर 'निर्धन हो या हो धनवान, कानून सभी के लिए समान' की अवधारणा का अनुपालन अपेक्षित होता है, किंतु यदि राजनीतिक स्वार्थों के कारण संविधान में समय समय पर संशोधन करके उसे राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बनाया जाए, तो यह स्थिति कि-सी भी राष्ट्र में मानवीय दृष्टिकोण से घातक सिद्ध हो सकती है। भारत में संविधान के साथ हुई छेड़छाड़ से ऐसा ही संदेश जनमानस को मिला है।

संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई । कितने जन-प्रतिनिधियों ने विशुद्ध रूप से संविधान पर चर्चा की और कितनों ने अपने राजनीतिक एजेंडे को सामने रखा, यह विश्लेषण का विषय है, मगर देश के संविधान को समय-समय पर तुष्टिकरण के लिए बदलने वाली कांग्रेस अब इसकी अधिक दहाई दे रही है। संसद में संविधान पर हुई बहस में नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष पर एकलव्यों का अंगूठा काटने का आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष यह भूल गए कि यदि किसी ने संविधान से सर्वाधिक छेड़छाड़ करके देश की पंथ निरपेक्षता को तार-तार किया है, तो वह कांग्रेस ही है। कभी इंदिरा गांधी की हत्या के उपरांत 1984 में निरीह सिखों का कत्लेआम हुआ, तो कभी वक्फ बोर्ड को विशेषाधिकार देकर सांप्रदायिक सौहार्द को तार-तार किया गया । कौन नहीं जानता कि शाह बानो प्रकरण में देश के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करते हुए मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने संबंधी आदेश की अवमानना की गई, यही नहीं, 1991 पूजा स्थल अधिनियम के माध्यम से पूजा स्थलों पर धर्म विशेष के अनुयायियों के अवैध कब्जो को सही ठहराने का प्रयास किया गया? रहा सवाल एकलव्यों का अंगुठा काटने का, तो एक ही वंश का वर्चस्व बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रतिभावान एकलव्यों का कितना सम्मान किया गया, यह किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस का वंशवादी इतिहास यदि खंगाला जाए तो स्पष्ट होगा कि इस पार्ट ने सिर्फ एकलव्यों का अंगुठा ही नहीं काटा, वरन उनका मर्दन भी किया है। धार्मिक तुष्टिकरण के नाम पर देश के सांप्रदायिक सौहार्द का कत्ल किया है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि समय- समय पर संविधान को अपने पैरों तले रौंदने वाली कांग्रेस आखिर किस मुंह से संविधान बचाने की दुहाई दे सकती है, जबकि संविधान से खिलवाड़ करने की सर्वाधिक दोषी वही है?

भारत अपनी शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाएं

कनाडा से अलग अन्य देशों का क्या हाल है? अपग्रेड अब्राड ने पचीस हजार छात्रों के डाटा की समीक्षा को जिन्होंने विदेश में शिक्षा ग्रहण करने में दिलचस्पी दिखाई है। यह डाटा पिछले साल जनवरी से जुलाई के बीच में एकत्र किया गया था। तब इनमें से 18 प्रतिशत में कनाडा में शिक्षा प्राप्त करने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन जब इस डाटा को पिछले साल जुलाई से दिसम्बर के बीच पुनः समीक्षा की गई तो यह दिलचस्पी घटकर लगभग आधी यानी 9.3 प्रतिशत रह गई, इसके विपरीत जर्मनी जैसा डेस्टिनेशन जहाँ प्रारम्भिक दिलचस्पी 19 प्रतिशत थी। अब वह बढ़कर 32 प्रतिशत हो गई है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नीदरलैंड व फिनलैंड के अतिरिक्त अब भारतीय छात्रों की दिलचस्पी ताइवान व इजरायल जैसे स्टडी डेस्टिनशंस में बढ़ती जा रही है क्यों कि ये देश अब भारतीय प्रतिभा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि-कनाडा के नए संशोधित नियमों व जीआईसी में दोगुनी वृद्धि के अलावा भारत कनाडा के बीच जो राजनीतिक खींच तान चल रही है, उससे भी यहां शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखने वाले छात्रों के सामने चुनौतियां बढ़ी हैं। विदेशों में रोजगार को लेकर पहले बात हमेशा बहस का मुद्दा हुआ करती थी कि भारत से प्रतिभा पलायन हो रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक पक्ष था। असल में भारत से बाहर जाकर विदेश में रोजगार करते वाले प्रवासी हर साल अपनी मात्रभूमि को 100 अरब डॉलर या इससे अधिक भेजते हैं। आज प्रवासी भारतीयों के देश प्रेम के कारण भारत दुनिया में सबसे अधिक रेमिटेंट हासिल करने वाला देश बन गया है। प्रवासी भारतीयों में 2022 में 110 अरब डॉलर रेमिटेंस अपने देश भेजा था। इसी तरह 2023 में बढ़कर यह 125 अरब डॉलर हो गया । इतनी बड़ी धनराशि जब विदेशी युवा के रूप में मिलती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को नई शक्ति प्रदान करती है।

विदेशों में सीमित अवसर :

अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में खड़ी की जा रही बाधाओं के मद्देनजर यह जरूरी हो गया है कि-भारत अब अपनी शिक्षा व्यवस्था को विश्वस्तरीय

बनाये क्योंकि, आज अगर दुनिया की तमाम बड़ी टेक कंपनियों में भारतीय ऊंचे-ऊंचे पदों पर बेठे हैं तो इसके पीछे उनकी बेहतरीन शिक्षा ही है। इसलिए भारत सरकार को आपदा में अवसर तलाशने की अपनी ध्रुव नीति को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने यहां विश्वस्तरीय शिक्षा संस्थान बनाकर छात्रों को आकर्षित करना चाहिए। इससे यहां की शिक्षा को बहुत फायदा होगा।

एक अनुमान के मुताबिक 2025 में लगभग 15 लाख छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं और ये फीस और अन्य मदों में 5.8 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इन छात्रों को भारत में हो विश्वस्तरीय

शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके तो लाखों छात्रों को रोका जा सकता है। इससे अरबों डॉलर जो विदेशी संस्थानों को जाता है वह भारतीय शिक्षा संस्थाओं के पास आएगा। इसमें सरकार खुद पहल करे और निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे विश्वस्तरीय शिक्षा संस्थान भारत में विकसित कर छात्रों को पलायन से रोकें।

विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने का सपना सिर्फ विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। वैश्विक स्तर पर अवसरों के विशाल फलक में

> धीरे-धीरे छात्रों पर पाबंदियां बढ़ रही हैं जिसके कारण विदेश में पढ़ने के फायदे भी कम होते आरहे हैं। विदेश में पढाई का सबसे बड़ा फायदा यहां उपलब्ध रोजगार के अवसरों का फायदा उठाना था। लेकिन अब धीरे-धीरे सभी देशों विशेषकर अमेरिका, यूरोप में ऐसी पाबंदियां लगाई जा रही हैं जिससे विदेशी छात्र आसानी से रोजगार न हाथिया सकें।

अपने लिए कुछ बेहतर हासिल कर कॅरियर में सफल होने का सपना भी इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब विदेशी शिक्षा की राह धीरे-धीरे कठिन होती जा रही है। डॉलर पाउंड या अन्य विदेशी मुद्रा में फीस चुकाने और रहन सहन का प्रबंध करने में कमजोर रुपए के कारण पहले से ही यह बहुत महंगा था। अब तो और तमाम अड़चने खड़ी हो गई हैं। कनाडा में शिक्षा और फिर नौकरी हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर लोग पंजाब और आस-पास से जाते थे। लेकिन कनाडा के साथ भारत के रखराब से बंधों का

असर भी लोगों के आने जाने पर पड़ेगा। अमरीका की राह भी ट्रंप के कारण कठिन होगी, यूक्रेन में मेडिकल पढ़ाई करने गए छात्रों के साथ जो कुछ हुआ वह सबको पता है। कहीं युद्ध का माहौल है, कही रिश्ते बिगड़ गए हैं तो कहीं अन्य बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। हजारों भारतीय छात्रों का विदेशी विश्वविद्यालयों (विशेषकर अंग्रेजी बोलने वालें देशों) में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना कठिन होता जा जा रहा है क्योंकि कनाड़ा व इंग्लैंड जैसे देशों ने विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के प्रवेश नियमों को सख्त और महंगा कर दिया है। यथा- कनाडा को ही लें-अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का दावा करते हुए कनाडा की सरकार ने अपने विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के प्रवेश नियमों में संशोधन किया है लेकिन इसका असली कारण प्रतीत होता है कि पिछले साल दिसंबर में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या साजिश को लेकर ओटावा और नई दिल्ली के बीच जो राजनीतिक रस्साकसी हुई थी यही उसी का परिणाम है।

संशोधित नियमों में सबसे प्रमुख गारंटी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट (जीआईएस) का दाम दस हजार कैनेडियन डॉलर्स से बढ़ाकर दोगुने से भी अधिक याने 20, 635 कैनेडियन डॉलर्स कर दिया है। जर्मनी व ऑस्ट्रेलिया ने भी आहिस्ता-आहिस्ता अपने-अपने जीआईएस में इजाफा किया है। वह हर साल जीआ-ईएस में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि करते रहे हैं।

मई-2023 में जर्मनी का वीजा अप्लाई करने के लिए 11,208 यूरो (लगभग 10 लाख रुपए) थे जबकि इससे पहले कैप दस हजार यूरो थी। एक अन्य घटनाक्रम में इंग्लैण्ड ने घोषणा की है कि-2024 से अंतर्राष्ट्रीय छात्र अपनी शिक्षा पूर्ण होने के दौरान अपने आश्रित परिवार को नहीं ला सकेंगे। कनाडा ने पहले छात्रों को छात्रों को आकर्षित करने के लिए जीआईसी कम रखी थी लेकिन अब उसको सरकार को एहसास हुआ है कि यह बढ़ते हाउसिंग खर्च व महंगाई को देखते हुए पर्याप्त नहीं हैं। जर्मनी व ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हर साल जीआईसी में 10 प्रतिशत को वृद्धि करते हैं, जिससे अधिक प्रभाव नही पड़ती है, लेकिन कनाडा के एक ही झटके में शत-प्रतिशत की वृद्धि करने से छात्रों को शॉक लगा है। इस परिवर्तन से सबसे अधिक कौन से छात्र प्रभावित होंगे? नए संशोधित नियमों के तहत कनाडा ने शिक्षा परमिट था छात्र वीजा की संख्या 4 लाख से घटाकर 3.6 लाख कर दिया है। अकेले भारत से ही 1.4 लाख छात्र कनाडा जाया करते थे जिनमें से लगभग 80 प्रतिशत वहां डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम करने के किए जाते थे।

अब से पहले कनाडा माडइग्रेट होने का छात्र स्टडी अब्रॉड विकल्प के रूप में किसी भी डिप्लोमा में प्रवेश ले लेता था जो वास्तव में कमजोर न शैक्षिक संस्था वाले देशों के छात्रों के लिए माइग्रेट करने का पासपोर्ट होता था जिसमें यह सुविधा होती थी कि छात्र अपनी शिक्षा पूरा करता रहता था और उसको जीवनसाथी वीजा वर्क परमिट लेकर काम करता रहता था। अब नए नियमों के तहत कनाडा ने कहा है कि - वह वीजा जीवन साथी तो जारी करेगा। लेकिन जीवन साथी को वर्क परमिट नहीं दिया जायेगा।

धीरे-धीरे छात्रों पर पाबंदियां बढ़ रही हैं जिसके कारण विदेश में पढ़ने के फायदे भी कम होते आरहे हैं। विदेश में पढाई का सबसे बड़ा फायदा यहां उपलब्ध रोजगार के अवसरों का फायदा उठाना था। लेकिन अब धीरे-धीरे सभी देशों विशेषकर अमेरिका, यूरोप में ऐसी पाबंदियां लगाई जा रही हैं जिससे विदेशी छात्र आसानी से रोजगार न हाथिया सकें।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादक: पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com